सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 190, नई दिल्ली । गुरुवार, 19 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है।

03 दिल्लीवालों को सोचना है कि केजरीवाल सीएम नहीं होंगे तो...
06 नीट युजी 2025: मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका, केंद्रित और शांत रहने की रणनीतियाँ
08 वन नेशन, वन इलेक्शन को मंजूरी: 191 दिन में तैयार रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए

दिल्ली में नए व्यवसायिक श्रेणी के वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली में अब व्यावसायिक वाहन खरीदने वालों को अपने वाहनों के पंजीकरण के लिए परिवहन विभाग के चक्कर नही लगाने पड़ेंगे। निजी वाहन डीलरो की तरह ही अब व्यावसायिक वाहन डीलर आपको वाहन का पंजीकरण देने लगेंगे। अब वाहन मालिकों को *दिल्ली में लागू आपके लिए आवश्यक

परमिट कंडीशन,

मोटर वाहन रूल के अनुसार रंग,

उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश

उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश

अन्य सरकारी विभागों के द्वारा जारी आदेश

जिनको पूरा कराने के बाद वाहन को फिटनेस शाखा पर चेक करवाने के बाद पंजीकरण की प्रक्रिया शुरु होती थी से छुटकारा मिल गया। अब आपको वाहन डीलर अपने कार्यालय से ही पंजीकरण करके वाहन और उसकी आरसी प्रदान कर

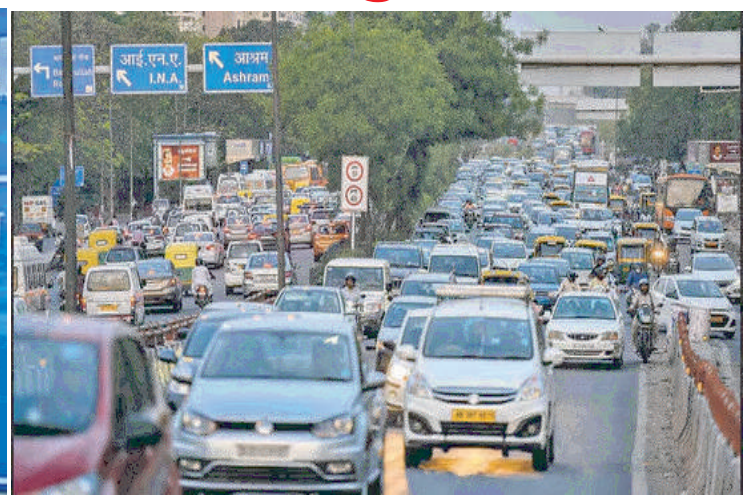

देगा। **है ना नया व्यावसायिक वाहन खरीदने वाले मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी** दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिकों को **दिल्ली के परिवहन आयुक्त और विशेष परिवहन आयुक्त का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि सभी आदेशों निर्देशों एडवाइजरी और नियमों से बिना कुछ कहे मुक्त कर दिया।** क्या पूरे विश्व में मिलेंगे ऐसे मददगार अधिकारी जो अपने राज्य के व्यवसायिक वाहन मालिकों को सुप्रीन कोर्ट, गृह सचिव के नेतृत्व की कमेटी, उच्च न्यायालय दिल्ली, मोटर वाहन नियम अधिनियम और धारा के अनुसार वाहन को पंजीकृत कराने से पहले के सभी से मुक्त कर दे। अब वाहन खरीदे और तत्काल ऑनलाइन परमिट अप्लाई कर प्राप्त कर वाहन को चलाना शुरू करे।

दिल्ली वेस्ट के निवासियों को मिलने वाली परिवहन विभाग की तीन शाखाओं से सुविधा जल्द हो जाएगी सिर्फ़ एक शाखा में

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली में पहले तीन शाखाओं को मुख्यमंत्री से ताला लगवाया फिर तीन शाखाओं को एक में परिवहन आयुक्त और विशेष आयुक्त ने कर दिया और अब फिर से परिवहन आयुक्त और विशेष परिवहन आयुक्त वजीरपुर शाखा, रोहिणी शाखा और मॉल रोड शाखा को एक शाखा में परिवर्तित करने के आदेश फाइल में जारी करने वाले हैं। अब दिल्ली वेस्ट की जनता को जो अभी रोहिणी शाखा या वजीर पुर शाखा या मॉल रोड शाखा में जाते हैं सभी को मॉल रोड शाखा में अपने वाहनों, लाइसेंस, बेज और कंडक्टर से सम्बंधित कार्यों के लिए जाना होगा या कहे तो धक्के खाने होंगे। **कितने जनहित के कार्य कर रहे हैं परिवहन आयुक्त, विशेष परिवहन आयुक्त, मंत्री परिवहन, मुख्यमंत्री परिवहन और साथ दे रहे हैं मुख्य सचिव दिल्ली एवम् उपराज्यपाल दिल्ली।**

रेड लाइन पर ओएचई टूटने से तीन घंटे प्रभावित रही मेट्रो, यात्रियों को हुई भारी परेशानी

संजय बाटला

दिल्ली मेट्रो के सबसे पुराने कॉरिडोर रेड लाइन पर मंगलवार को तीन घंटे के लिए यात्री सेवा प्रभावित रही। जिस कारण से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें रेड लाइन पर ओएचई टूटने से तीन घंटे तक मेट्रो का परिचालन प्रभावित रहा। इस दौरान यात्रियों ने कहा कि 20 मिनट इंतजार के बाद भी मेट्रो उपलब्ध नहीं हुई। पढ़ें DMRC ने क्या कहा।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो के सबसे पुराने कॉरिडोर रेड लाइन (रिठाला-दिलशाद गार्डन-शहीद स्थल) पर ओएचई (ओवर हेड इक्विपमेंट) टूटने से मंगलवार को दोपहर में तीन घंटे मेट्रो का परिचालन प्रभावती रहा।

इससे यात्रियों को सफर में परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में काफी देरी हुई। ओएचई ठीक होने के बाद शाम करीब चार बजे रेड लाइन पर मेट्रो का परिचालन सामान्य हुआ।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) के अनुसार 34.55 किलोमीटर लंबी रेड लाइन पर दोपहर 1:04 बजे प्रताप नगर और शास्त्री नगर स्टेशन के बीच मेट्रो का ओएचई टूट गया। इस वजह से रिठाला की ओर जा रही मेट्रो ट्रेन रुक गई।

इससे दोनों स्टेशनों के बीच मेट्रो के डाउन ट्रैक (शहीद स्थल से रिठाला की ओर) मेट्रो का परिचालन अचानक ठप हो गया। कुछ देर बाद इंद्रलोक से तीस हजारी के बीच सिंगल लाइन पर मेट्रो का परिचालन शुरू किया गया। इस वजह से ओएचई मरम्मत होने तक रेड लाइन पर तीन लूप में मेट्रो चली।

रिठाला से इंद्रलोक और तीस हजारी से शहीद स्थल के बीच अप और डाउन दोनों तरफ से मेट्रो का परिचालन जारी रखा गया। ओएचई (OHE) के मरम्मत कार्य के कारण इंद्रलोक से तीस हजारी के बीच सिंगल लाइन पर ही दोनों तरफ की ट्रेनों का बारी-बारी परिचालन हुआ।

इस वजह से मेट्रो ट्रेनें देर से उपलब्ध हो पा रही थीं। इसका असर रेड लाइन के पूरे हिस्से पर पड़ा। इस वजह से तीस हजारी, इंद्रलोक, शास्त्री नगर, प्रताप नगर, पुल बंगश के अलावा कश्मीरी गेट सहित कई स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई।

नीरज कुमार नाम एक यात्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कश्मीरी गेट स्टेशन पर रिठाला की तरफ जाने के लिए दो मेट्रो ट्रेनें आईं लेकिन कश्मीरी गेट स्टेशन पर नहीं रुकीं।

इस वजह से वह कश्मीरी गेट स्टेशन पर फंसे हुए हैं। हार्दिक कौशिक नामक व्यक्ति ने पोस्ट कर कहा कि मेट्रो का परिचालन रुक गया है और सभी यात्री तीस हजारी स्टेशन पर मेट्रो से उतार लिए गए हैं।

20 मिनट इंतजार के बाद भी मेट्रो उपलब्ध नहीं हुई। प्रवीन कुमार नामक यात्री ने कहा कि एसएससी की परीक्षा थी। रेड लाइन पर मेट्रो का परिचालन प्रभावित होने से उन्हें स्टेशन पर पहुंचने में देरी हो गई।

एक अन्य यात्री ने भी यह शिकायत की। डीएमआरसी का कहना है कि दोपहर 3:51 बजे ओएचई ठीक कर लिया गया। इसके बाद परिचालन सामान्य हुआ।

दिल्ली मेट्रो फेज-4: चौथे चरण की सबसे लंबी सुरंगों का खोदाई का काम पूरा, जानिए जमीन से कितनी नीचे दौड़ेगी मेट्रो

दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत मजेंटा लाइन पर बन रहे जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मेट्रो कॉरिडोर पर डेरावल नगर को पुलबंगश से जोड़ने वाली तीन किलोमीटर लंबी दो समानांतर सुरंगों की खोदाई का काम पूरा हो गया है। यह दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी सुरंग है। दोनों सुरंग जमीन की सतह से लगभग 15 मीटर की गहराई पर बनाई गई हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मेट्रो कॉरिडोर पर डेरावल नगर को पुलबंगश से जोड़ने वाली तीन किलोमीटर लंबी दो समाानांतर सुरंगों की खोदाई का काम पूरा हो गया है। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत मजेंटा लाइन पर इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस चरण की यह सबसे लंबी सुरंग हैं।

दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र और दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के प्रबंधक निदेशक डॉ. विकास कुमार की उपस्थिति में बुधवार को पुलबंगश मेट्रो स्टेशन पर दो टनल बोरिंग मशीनें (टीबीएम) 'भूमि' और 'सृष्टि', एक साथ बाहर निकाली गईं। पहली बार समानांतर सुरंग खोदने का काम एक साथ पूरा किया गया है।

एक दिन में आठ मीटर हुई खोदाई

सुरंगों का आंतरिक व्यास 5.8 मीटर है। आपात स्थिति में इन्हें आपस में जोड़ने के लिए छह क्रॉस-पैसेज का निर्माण किया गया है। मात्र 14 माह में ही प्रति टनल प्रति दिन औसतन 8.2 मीटर की गति से लगभग 2997 मीटर टनल खोदाई का कार्य किया गया।

जमीन से 15 मीटर नीचे सुरंग

दोनों सुरंग जमीन की सतह से लगभग 15 मीटर की गहराई पर बनाई गई हैं। यह राणा प्रताप बाग और पंजाबी बस्ती कॉलोनी जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों के साथ ही नजफगढ़ नाले के नीचे से भी गुजरेंगी। नाले के कारण यह एक संवेदनशील खंड है। इसके बाद भी सुरंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक (कारपोरेट कम्युनिकेशंस) अनुज दयाल ने बताया कि इससे पहले 21 अगस्त को दिल्ली एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर की छतरपुर मंदिर क्षेत्र में टीबीएम का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान: #VocalForLocalRoadSafety

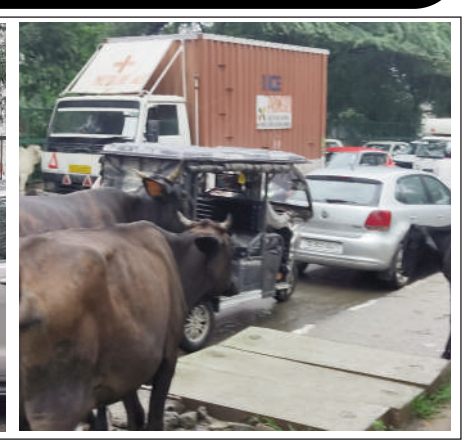

स्थान: मथुरा रोड, दिल्ली से फरीदाबाद रोड

जाम का मुख्य कारण: गलत दिशा में गाड़ी चलाना और सड़क के बीच बैठे आवारा पशु

मथुरा रोड पर, खासकर दिल्ली से फरीदाबाद के टोल रोड की ओर बढ़ते हुए, सरिता विहार से फरीदाबाद तक की सड़क पर ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या देखी जा रही है। 18 सितंबर को भी इस मार्ग पर जाम का मुख्य कारण आवारा पशु और गलत दिशा में वाहन चलाने की प्रवृत्ति रहा। आली गांव कट पर यह समस्या और भी विकट हो जाती है, जहाँ सड़क के बीचों-बीच बैठे पशु और वाहन चालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए गलत दिशा में गाड़ी चलाना ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण बने हुए हैं।

समस्या का मुख्य कारण:

आवारा पशु: कई आवारा गाय, कुत्ते और अन्य पशु सड़क के बीच बैठ जाते हैं, जिससे न केवल ट्रैफिक रुक जाता है, बल्कि हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है।

गलत दिशा में वाहन चलानाः आली गांव कट के पास अक्सर लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं, जिससे यातायात अव्यवस्थित हो जाता है।

ट्रैफिक पुलिस की कमी: इस क्षेत्र में नियमित निगरानी की कमी से यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।

ट्रैफिक जाम के प्रभाव:

यातायात ठप हो जानाः खासकर ऑफिस के समय में लोग घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं, जिससे समय और ईंधन की बर्बादी होती है।

सड़क सुरक्षा पर असर: आवारा पशुओं के कारण कई बार सड़क हादसे हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस को इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता:

आवारा पशुओं की व्यवस्थाः स्थानीय निकायों और दिल्ली पुलिस को मिलकर आवारा पशुओं के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वे सड़कों पर न बैठ सकें।

नियमित ट्रैफिक चेकिंग: आली गांव कट पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और नियमित ट्रैफिक चेकिंग की जाए।

सीसीटीवी निगरानी: इस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

स्थानीय जागरूकता अभियान: सड़क सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों और वाहन चालकों के बीच जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोग नियमों का पालन करें।

मथुरा रोड पर आवारा पशुओं और गलत दिशा में गाड़ी चलाने की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन को त्वरित कदम उठाने होंगे। इससे न केवल सड़क सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि जाम की समस्या से भी निजात मिल सकेगी।

आतिशी का चुनाव सुनीता से बेहतर, किंतु कांटों से भरा ताज

आतिशी मार्लेना

ओंकारेश्वर पांडेय

दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी को सत्ता का सुखदायी सिंहासन नहीं बल्कि चुनौतियों और कांटों से भरा ताज मिला है। मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के सामने अनेक चुनौतियाँ होंगी जो न केवल उनकी प्रशासनिक क्षमता की परीक्षा लेंगी, बल्कि उनकी राजनीतिक सूझ-बूझ और नेतृत्व क्षमता का भी सख्त इम्तिहान होंगी।

अपनी पत्नी और आम आदमी पार्टी की एक कद्दावर नेता बन चुकी नेता सुनीता केजरीवाल को दरकिनार कर आतिशी मार्लेना का चुनाव करके पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अगर वे सुनीता केजरीवाल को चुनते तो उनके ऊपर भी लालू यादव की तरह, बिना अनुभव के सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देने और पार्टी में लोकतंत्र खत्म कर देने जैसे आरोप लगाये जाते। सुनीता केजरीवाल ने पति और पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के जेल के दिनों के मुश्किल राजनीतिक दौर में उनका और पार्टी का पूरा साथ समर्थन तो दिया, लेकिन आतिशी का चुनाव शुद्ध रूप से उनके प्रशासनिक अनुभव, साफ छवि, और सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ केजरीवाल के प्रति उनकी पूर्ण वफादारी के कारण सर्वाधिक उपयुक्त माना जा रहा है। हालांकि आतिसी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी सत्ता का सुखदायी सिंहासन नहीं बल्कि चुनौतियों और कांटों से भरा ताज मिला है।

बेहतर कैसे हैं आतिशी ?

आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य कई वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य हो सकते थे, लेकिन उनके खिलाफ लगे विभिन्न आरोप और कुछ अन्य कारणों से शायद वे इस पद के लिए चयनित नहीं हुए।

1. **उप मुख्यमंत्री तथा शिक्षा और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया:** पार्टी में दूसरे नंबर के बड़े नेता मनीष भी दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी हैं और गिरफ़्तार भी हो चुके हैं।

2. **स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन:** दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक की सफलता के लिए जाने जाने वाले सत्येंद्र जैन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था।

3. **परिवहन और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय:** गोपाल राय एक अनुभवी और प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन जनाधार सीमित है और किसी बड़े प्रशासनिक सुधार या योजना में उतनी प्रमुख भूमिका नहीं रही है।

4. **कैलाश गहलोत:** गहलोत पर भी कुछ विवादास्पद जमीन सौदों से जुड़े आरोप हैं।

5. **सुनीता केजरीवाल:** अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी नाम संभावित उम्मीदवारों में था, लेकिन उनका प्रशासनिक अनुभव सीमित है और राजनीति में उनकी कोई सीधी भूमिका नहीं रही है।

आतिशी की छवि साफ है, प्रशासनिक अनुभव मजबूत है और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान प्रमाणित है। उनका चयन पार्टी को स्वच्छ और प्रगतिशील नेतृत्व देने के अवसर के साथ विपक्ष के आरोपों का भी माकूल जवाब है।

चुनौतियों और कांटों से भरा ताज

हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी को सत्ता का सुखदायी सिंहासन नहीं बल्कि चुनौतियों और कांटों से भरा ताज मिला है। मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के सामने अनेक चुनौतियाँ होंगी जो न केवल उनकी प्रशासनिक क्षमता की परीक्षा लेंगी, बल्कि उनकी राजनीतिक सूझ-बूझ और नेतृत्व क्षमता का भी सख्त इम्तिहान होंगी।

सबसे बड़ी चुनौती सुशासन की होगी, जो दिल्ली के आम आदमी की जमीनी समस्याओं से जुड़ी है— चाहे वह पानी की किल्लत हो, प्रदूषण का मुद्दा हो, या स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के निरंतर प्रयास।

इसके अलावा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ तालमेल बैठाना, जो अक्सर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव का कारण बनता है, भी आतिशी के लिए एक प्रमुख चुनौती होगी।

अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा था, ₹आतिशी भारतीय राजनीति में सबसे उज्ज्वल दिमागों में से एक हैं। उनका शिक्षा व्यवस्था में सुधारों का कार्य अतुलनीय है, और उनमें दिल्ली को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है।₹ केजरीवाल का उनके प्रति यह भरोसा स्पष्ट है, लेकिन एक सुधारक से लेकर एक राजनीतिक नेता बनने तक की यात्रा, जो दिल्ली जैसे जटिल शहर की पूरी शासन संरचना को संभालेगी, एक कठिन कार्य होगा।

सुशासन, शिक्षा सुधार, और महिला सशक्तिकरण की प्रमुख कर्ताधर्ता रहीं आतिशी मार्लेना दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में कम उम्र में राजनीति की उस ऊंचाई पर जा खड़ी हुई हैं, जहां पहुंचने के लिए अनेक नेता अपना पूरा राजनीतिक जीवन लगा देते हैं। राजनीतिक लचीलेपन, बौद्धिक दृष्टिकोण और सुधारवादी नीतियों से भरी उनकी यात्रा और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का उनके प्रति विश्वास ने उन्हें दिल्ली की नेतृत्व भूमिका में ला दिया है, जो एक लाइफ टाइम एचीवमेंट और स्वर्णिम अवसर है।

मुख्यमंत्री पद की चुनौती उनके नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमताओं और राजनीतिक कौशल की नई परीक्षा तो होंगी ही पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को संभालना, विपक्ष के हमलों का प्रभावी जवाब देना और पार्टी की छवि को बनाए रखना भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा।। बावजूद इसके कि उन्हें केजरीवाल का समर्थन प्राप्त है, यह अवसर उनके लिए महत्वपूर्ण भी है और चुनौती पूर्ण भी। देखना होगा कि वह इन कड़ी चुनौतियों से कैसे निपटती हैं और दिल्ली की जनता का विश्वास कैसे जीतती हैं।

शैक्षिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि

आतिशी की बौद्धिक क्षमता उनके शैक्षणिक उपलब्धियों और प्रगतिशील शिक्षित परिवार की पृष्ठभूमि से आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास की पढ़ाई को बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से चेवेनिंग स्कॉलर के रूप में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त आतिशी के माता-पिता विजय सिंह और त्रिप्ता वाही, दोनों शिक्षक और समाजसेवी रहे हैं। परिवार में बचपन से ही राजनीति, सामाजिक न्याय और शिक्षा पर चर्चा होती थी, जिसने उन्हें समाज सेवा के लिए प्रेरित किया और राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया।

जब केजरीवाल जेल में थे

जब केजरीवाल, सिसोदिया व संजय सिंह से लेकर पार्टी के कई बड़े नेता जेल में थे, और दिल्ली सरकार में नेतृत्व का अभाव सा था, तो आतिशी ने इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक संभाल कर अपनी प्रशासनिक क्षमता साबित की, जिससे पार्टी में उनके प्रति विश्वास और मजबूत हुआ।

प्रशासनिक चुनौतियाँ

आतिशी की भूमिका बतौर सलाहकार मनीष सिसोदिया के तहत शिक्षा में सुधार करने की रही है। उनकी देखरेख में हैप्पीनेस करिकुलम और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम जैसे सुधार किए गए, जिन्हें दिल्ली व देश समेत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया।

हालांकि, अब मुख्यमंत्री आतिशी को दिल्ली के पूरे प्रशासनिक तंत्र को संभालना ज्यादा चुनौती भरा होगा। दिल्ली के कई महत्वपूर्ण विभाग लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र सरकार के अधीन होते हैं— और तकरार होती रहती है। उसमें सफलतापूर्वक नेविगेट करना उनके प्रशासनिक कौशल की असली परीक्षा होगी।

राजनीतिक चुनौतियाँ

आतिशी की राजनीतिक यात्रा में कठिनाइयाँ भी रही हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के गौतम गंभीर से हारना उनके लिए बड़ा झटका था। इस हार ने दिखाया कि उन्हें जनाधार बढ़ाने और मजबूत राजनीतिक व्यक्तित्व के निर्माण की आवश्यकता है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में कालकाजी से उनकी जीत ने उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया।

स्वाति मालीवाल का मुद्दा

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही स्वाति मालीवाल द्वारा केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार पर लगाये आरोपों और केजरीवाल द्वारा उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देने को कहने के बीच जारी विवादों के आलोक में भी आतिशी का मुख्यमंत्री बनना यह साबित करेगा कि AAP प्रगतिशील नेतृत्व, लैंगिक समानता और स्वच्छ शासन के लिए प्रतिबद्ध है।

विपक्ष की आलोचना का जवाब

मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी का चुनाव एक अहम रणनीतिक कदम भी है और बीजेपी और कांग्रेस द्वारा पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की आलोचनाओं का जवाब भी। अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा था, ₹AAP सिर्फ एक पार्टी नहीं है, यह एक आंदोलन है।₹ केजरीवाल ने यह साफ संदेश दिया है कि AAP भविष्य के लिए नए नेताओं को तैयार कर रही है जो पार्टी को आगे ले जा सकते हैं।

निर्णायक क्षण

दिल्ली की मुख्यमंत्री बनना आतिशी मार्लेना के लिए एक निर्णायक क्षण है। आतिशी ने कहा है, ₹अच्छा शासन केवल नीतियों के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है।₹ इस कथन में उनका मानवीय दृष्टिकोण स्पष्ट है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनके धैर्य, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा होगी। अगर वह इन चुनौतियों से पार पाती हैं, तो वह न केवल दिल्ली की एक प्रमुख नेता बनेंगी, बल्कि भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय भी लिखेंगी।

(लेखक एक प्रसिद्ध पत्रकार, राष्ट्रीय सहारा के पूर्व वरिष्ठ समूह संपादक, पूर्व संपादक-एएनआई, राजनीतिक टिप्पणीकार, रणनीतिकार, जम्मू-कश्मीर मामलों के अध्येता और विचारक हैं।)

अर्थशास्त्र, लेखा और वित्त सेवाओं में कैरियर के अवसर

विजय गर्ग

अकाउंट्स और फाइनेंस सेक्शन को हर व्यावसायिक गतिविधि की रीढ़ माना जाता है, चाहे वह छोटे पैमाने पर व्यापार इकाई हो जो छोटे ग्रामीण इलाके में काम कर रही हो या बहुराष्ट्रीय कंपनी हो, जिसकी व्यापारिक गतिविधियां लगभग पूरी दुनिया में हों। लेखांकन और वित्तीय लेनदेन को शामिल किए बिना व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में सोचना अकल्पनीय है और वर्तमान परिदृश्य में तो बिल्कुल भी नहीं, जब पूरे विश्व ने एक बाजार का दर्जा हासिल कर लिया है। आज जब वैश्वीकरण चर्चा का विषय बन गया है, तो वित्त में बहुत संभावनाएं हैं - इसलिए वैश्विक मंदी के बावजूद ₹वित्त और लेखा₹ - दो अलग लेकिन सहसंबद्ध क्षेत्र - न केवल एक विषय के रूप में बल्कि एक कैरियर विकल्प के रूप में भी रोमांचक हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था का व्यापक विस्तार। बैंकिंग कंपनियों के इतनी तेज गति से बढ़ने से अकाउंट और वित्त के इस क्षेत्र में नए प्रवेशकों को कोई निराशा नहीं होगी। आने वाले कुछ वर्षों में निचले स्तर से प्रशिक्षित पेशेवरों की बड़ी मांग होगी दुनिया भर में स्थापित होने वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की लेखांकन और वित्तीय गतिविधियों की देखरेख के लिए शीर्ष प्रबंधन स्तर पर युवा पीढ़ी अपने पेशेवर प्रशिक्षण और शिक्षा के स्तर के अनुसार इस कैरियर विकल्प में एक महान भविष्य की उम्मीद कर सकती है पदानुक्रम एक ₹लेखाकार₹ से शुरू होकर एक ₹वित्तीय सलाहकार₹ तक होता है, अर्थात, वित्त विभाग के शीर्ष पर या एक ₹मुख्य वित्त अधिकारी₹ जो एक व्यावसायिक इकाई के लेखा विभाग में वित्तीय सलाहकार के समकक्ष होता है, जिसमें नीचे कई मध्य स्तर शामिल होते हैं- दो चरम सीमाओं के बीच नौकरियां दी गईं। इस क्षेत्र से जुड़ने की इच्छुक युवा पीढ़ी आगे दिए गए किसी एक क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। वित्त प्रबंधन किसी भी संगठन की रीढ़ है चाहे वह कॉर्पोरेट हो, बड़ा व्यावसायिक घराना हो या वित्तीय संस्थान हो। हालांकि यह एक सफल और लाभदायक व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण पहलू है, वित्तीय प्रबंधन वित्तीय योजना से लेकर बिक्री तक नौकरी के कई विकल्प प्रदान करता है। इक्विटीः मूल रूप से एक बुक-बिल्डिंग प्रक्रिया है जो इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड पेशकशों/आईपीओ आदि के हामीदार के रूप में सेवाएं प्रदान करती है, और पूरे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नवीन संरचित उत्पाद प्रदान करती है। वित्तीय बाजारों के इस उपडोमेन में प्रवेश करने के लिए बायबैक निष्पादित करने में विशेषज्ञता और स्थानीय बाजारों और वैश्विक संसाधनों का व्यापक ज्ञान आवश्यक है। ऋण बिक्रीः इस क्षेत्र के पेशेवर संस्थागत निवेशकों और कॉर्पोरेट को विभिन्न निश्चित आय उत्पाद-निश्चित आय और म्यूचुअल फंड उत्पाद वितरित करते हैं जिनमें वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, बैंक, म्यूचुअल फंड, विदेशी संस्थागत निवेशक, भविष्य / ग्रेच्युटी फंड, धार्मिक / शैक्षिक / शामिल हैं। धर्मार्थ ट्रस्ट. निवेश बैंकिंगः ग्राहकों को नवीन ऋण और इक्विटी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से पूंजी बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना। उम्मीदवारों के पास अंडरराइटर और सिक्योरिटीज ब्रोकर के रूप में अनुभव होना चाहिए। एक निवेश बैंक ग्राहकों को उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए नवीन समाधान प्रदान करना चाहता है। स्टॉक बाज़ार, स्टॉक ब्रोकर और निवेश विश्लेषकः सेबी द्वारा अधिग्रहण और भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों की आमद ने स्टॉक ब्रोकरिंग और निवेश विश्लेषकों में करियर के अवसर तलाशने वाले पेशेवरों के लिए इसे रोमांचक और सुरक्षित बना दिया है। स्टॉक एक्सचेंजों के निगमीकरण ने इस क्षेत्र को और अधिक परिपक्व होते देखा हैपेशेवर। बाज़ारों में कई नए उपकरण पेश किए गए हैं, जिनमें सूचकांक वायदा, सूचकांक विकल्प, डेरिवेटिव और चुनिंदा शेयरों में विकल्प और वायदा शामिल हैं। इक्विटी विश्लेषक के रूप में करियर में रुचि रखने वाले लोग भारत के हैदराबाद में स्थित द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित इक्विटी अनुसंधान और विश्लेषण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम अपना सकते हैं। वाणिज्य में स्नातक ब्रोकर का पेशा अपना सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में सदस्यता प्राप्त करने के लिए, किसी को ब्रोकिंग फर्म के तहत कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण से गुजरना होगा। वेंचर कैपिटलः वित्त पेशेवरों के लिए इस क्षेत्र में करियर की काफी संभावनाएं हैं क्योंकि भारत एशिया प्रशांत (जापान को छोड़कर) में तीसरा सबसे सक्रिय उद्यम पूंजी बाजार है। निरंतर विनियमन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप 2015 तक भारतीय वित्तीय सेवाएँ लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। लेखांकन या वित्तीय प्रबंधक किसी कंपनी की वित्तीय रणनीति और इतिहास की देखरेख और रखरखाव के लिए जिम्मेदार लोग होते हैं। लेखांकन प्रबंधक वित्तीय रिपोर्टिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वित्तीय प्रबंधक रणनीति और धन प्रबंधन पर केंद्रित होता है। वित्तीय विश्लेषक और प्रबंधक अपने निर्णय लेने में पिछले लेखांकन डेटा का उपयोग करते हैं, हालांकि, वित्तीय प्रबंधक की नंबर एक भूमिका कंपनी को निर्णय लेने, व्यवसाय विकास, रणनीतिक योजना बनाने में मदद करने के लिए वित्तीय विश्लेषण और

रिपोर्ट के उत्पादन की निगरानी करना है। गठबंधन प्रबंधन. इन रिपोर्टों के उपयोग के माध्यम से, वित्तीय विश्लेषक कंपनी के निवेश और व्यवसाय विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय विश्लेषक द्वारा विकसित और कार्यान्वित नकदी प्रबंधन रणनीतियाँ कंपनी को कुशलतापूर्वक बढ़ने में मदद करती हैं और उसे अपने निवेश में अधिकतम लाभप्रदता प्राप्त करने की अनुमति देती हैं। दूसरी ओर कॉर्पोरेट सेटअप में काम करने वाले लेखा प्रबंधक नियंत्रक और लेखापरीक्षा समूहों के अंदर आय विवरण बनाने के अलावा कर रिपोर्टिंग और प्रबंधन से संबंधित कार्य करते हैं। यह करियर पथ किसी को कॉर्पोरेट कोषाध्यक्ष, कॉर्पोरेट नियंत्रक, या सीएफओ (मुख्य वित्त अधिकारी) के पद तक पहुंचा सकता है। सार्वजनिक लेखा कंपनी के लिए काम करने वाले पेशेवर एकाउंटेंट स्वतंत्र ऑडिट या कर सलाहकारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के समान कार्य करेंगे। लेखांकन में आधारित एक शैक्षिक इतिहास या पृष्ठभूमि, या तो मास्टर डिग्री या वित्त एमबीए के रूप में, आपको सीपीए (प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार) परीक्षा देने के लिए आवश्यक कुछ पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। कॉर्पोरेट नियंत्रक कंपनी की वित्तीय स्थिति का पूर्वानुमान लगाने और उसे संकलित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के प्रभारी होते हैं। इसके अलावा, एक नियंत्रक अक्सर किसी कंपनी के बजट, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग विभागों का प्रभारी होगा। मुख्य वित्तीय अधिकारीः किसी संगठन का शीर्ष वित्तीय कार्यकारी कंपनी की वित्तीय नीतियों और रणनीतियों के प्रशासन के साथ-साथ सभी लेखांकन और वित्तीय कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। एक छोटे पैमाने की कंपनी में सभी वित्तीय और प्रबंधन कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार होते हुए भी सीएफओ कुछ या सभी जिम्मेदारियां कंपनी के अन्य प्रबंधकों या उपाध्यक्षों को सौंप सकता है। सीएफओ और कोषाध्यक्षों के अलावा अन्य वित्त अधिकारी कंपनी के वित्तीय उद्देश्यों और बजट की देखरेख और मार्गदर्शन करते हैं। वित्तीय अधिकारी पूंजी जुटाने, नकदी प्रबंधन की देखरेख करने या कंपनी की पूंजी निवेश गतिविधि का प्रबंधन करने के लिए रणनीति बना और कार्यान्वित कर सकता है। वित्तीय अधिकारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैंकिसी कंपनी के विलय/विघटन और अधिग्रहण गतिविधियों में इसकी भूमिका। नकदी प्रबंधक नकदी प्रवाह की देखरेख और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं। वह यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार है कि कंपनी की नकदी स्थिति वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जोखिम और बीमा प्रबंधकः व्यवसाय संचालन और लेनदेन में एक निश्चित मात्रा में जोखिम शामिल होता है। जोखिम प्रबंधक और बीमा प्रबंधक किसी कंपनी को होने वाले नुकसान की मात्रा और जोखिम की मात्रा को कम करने के लिए काम करते हैं। प्रबंधन सलाहकार कंपनियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं और मुद्दों से बाहर निकलने में मदद करने के लिए काम करते हैं। ये मुद्दे कंपनी की लाभप्रदता में सुधार से लेकर कॉर्पोरेट पुनर्गठन और वित्तीय रणनीति बनाने तक कुछ भी हो सकते हैं। इस क्षेत्र में जाने वाले एमबीए को या तो ज्ञान के व्यापक आधार की विशेषज्ञ समझ होनी चाहिए या दो या दो से अधिक उपसमूहों में अत्यधिक कुशल होना चाहिए। प्रबंधन सलाहकार कंपनियों को नकदी प्रबंधन और उभरते बाजार विश्लेषण में भी मदद करेगा। निवेश बैंकर विस्तार के लिए पूंजी की आवश्यकता वाले निगमों और निवेश के लिए पूंजी वाले संस्थानों या निवेशकों के साथ एक साथ काम करेंगे। इस क्षेत्र में एमबीए एक बहुत बड़ी संपत्ति है क्योंकि निवेश बैंकर अपने ग्राहकों को पूंजी जुटाने के संबंध में निवेश सलाह देगा। अधिकांश निवेश बैंकों के पास एक कॉर्पोरेट वित्त प्रभाग होता है जो ग्राहकों को पूंजी जुटाने के लिए स्टॉक/शेयर या बांड जैसे वित्तीय साधनों की संरचना में सहायता करता है। निवेश बैंकिंग एसोसिएट्सः वित्त में नए एमबीए आम तौर पर एक विश्लेषक के रूप में प्रवेश स्तर की स्थिति से एक स्तर ऊपर होते हैं जो आमतौर पर केवल स्नातक की डिग्री वाले व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। निजी ग्राहकों के लिए इक्विटी अनुसंधान और परामर्श को भी अक्सर निवेश बैंकिंग पर ध्यान देने के साथ एमबीए के लिए करियर पथ के रूप में चुना जाता है। निवेश बिक्री सहयोगी और व्यापारी स्टॉक और बॉन्ड जैसी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री में कॉर्पोरेट या संस्थागत निवेशकों की सहायता करते हैं। बिक्री सहयोगी सिफारिशें करता है और विश्लेषण में मदद करता है, जबकि व्यापारी वास्तव में ग्राहक के लिए ऑर्डर निष्पादित करता है। क्रेडिट प्रबंधक और विशेषज्ञ उस क्रेडिट के प्रबंधन के प्रभारी होते हैं जो कोई कंपनी अपने ग्राहकों या अन्य को जारी कर सकती है। क्रेडिट प्रबंधक रेटिंग जोखिम और क्रेडिट के लिए मानदंड तैयार करते हैं, पेशकश करने के लिए क्रेडिट की अधिकतम राशि निर्धारित करते हैं, और पिछले देय खाता संग्रह की निगरानी करते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वह होता है जो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और कराधान में विशेषज्ञ होता है। वह प्रबंधन और कॉर्पोरेट कार्यवाहक के रूप में भी कार्य करते हैं। हाल के दिनों में अकाउंटेंसी एक पेशे के रूप में लोकप्रिय हो गई है। हमारे जैसे आर्थिक रूप से विकासशील देश में पूंजी और मुद्रा बाजारों की तीव्र वृद्धि के साथ-साथ व्यापार और उद्योग के बढ़ते महत्व ने खातों और वित्त पेशेवरों के महत्व को बढ़ा दिया है, जिससे यह न केवल भारत में शामिल होने और अपना भाग्य बनाने के लिए एक आकर्षक कैरियर पहलू बन गया है। बल्कि इंग्लैंड, वेल्स और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी क्योंकि भारत में सीऐ जैसे वित्तीय प्रशिक्षण संस्थान इंग्लैंड, वेल्स और ऑस्ट्रेलिया के संस्थानों द्वारा अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त हैं। आईसीएआई के सदस्य इन देशों में प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर रोजगार के लिए जा सकते हैं। चूंकि आईसीएआई इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स कमेटी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का सदस्य है, इसलिए कोई भी इन देशों में अपनी सेवाएं दे सकता है। लेकिन अभ्यास के लिए उन्हें संबंधित देशों द्वारा आयोजित एक विशेष परीक्षा से गुजरना होगा। युएनऐ द्वारा आयोजित परीक्षा को सीपीऐ, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट कहा जाता हैपरीक्षा.

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट - 152107

शपथ की तारीख पर आतिशी ने दिया अहम बयान, आज ही सामने आई थी यह डेट

राजधानी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुनी गई आतिशी ने शपथ ग्रहण को लेकर बड़ा बयान दिया है। आतिशी ने कहा कि अभी उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है। वैसे 21 सितंबर शनिवार को आतिशी के शपथ लेने की सूचना है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद ही आप विधायकों की बैठक में आतिशी को सीएम बनाने पर मुहर लगी थी।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठकों में दिल्ली की सीएम चुनी गई आतिशी ने कहा कि अभी शपथ ग्रहण की तिथि को लेकर कोई सूचना नहीं मिली है।

वहीं, सूचना आई है कि आतिशी 21 सितंबर शनिवार को सीएम पद की शपथ लेंगी। इसके बाद आतिशी दिल्ली की जनता के लिए काम करना शुरू कर देंगी।

केजरीवाल ने एलजी को सौंपा था इस्तीफा

अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बनने जा रही हैं। उनके शपथ लेने की तारीख भी सामने आ गई है। उन्होंने मंगलवार को एलजी से मिलकर सीएम बनने का दावा पेश किया था। वहीं, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा भी एलजी को सौंपा था।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भेज दिया है। वहीं, राष्ट्रपति को भेजे पत्र में 21 सितंबर को मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण की तारीख भी प्रस्तावित की है।

आप विधायक दल ने नहीं दी कोई तारीख

आप विधायक दल ने मनोनीत मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कोई तिथि प्रस्तावित नहीं की है। केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया।

नए-पुराने मंत्री लेंगे शपथ

बताया जाता है कि तकनीकी रूप से सीएम के इस्तीफा देने पर पूरी कैबिनेट भंग हो जाती है। इसलिए आतिशी के साथ-साथ उनकी कैबिनेट के सभी नए-पुराने सदस्य भी फिर से शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में सीमित अतिथि ही आमंत्रित होंगे। मंत्रियों के नाम और उनके विभाग तय करने का अधिकार भावी मुख्यमंत्री का ही होगा।

26 और 27 सितंबर को होगा विधानसभा सत्र

सरकारी सूत्रों के मुताबिक 26 और 27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। इस दौरान नई मुख्यमंत्री आतिशी विश्वास मत भी पेश कर सकती हैं। इसके अलावा विधायी प्रक्रिया पूरी करने के साथ साथ ही दिल्ली से जुड़े कुछ मुददों पर चर्चा भी की जा सकती है।

स्पोर्ट्स अथॉरिटी को देश को अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी देने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए : मनीष सिसोदिया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर स्थित स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में आयोजित जोनल एथलेटिक मीट में बतौर मुख्य आतिथि भाग लिया। इसमें सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया और अपने-अपने बैंड का प्रदर्शन कर सबको मंत्र गुग्ध कर दिया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भविष्य के ओलंपियंस तैयार हो रहे हैं। मैं लगभग डेढ़ साल से शिक्षा के कामों से दूर था और मुझे डर लग रहा था कि कहीं स्कूलों में काम पीछे न छूट गया हो, लेकिन मुझे यह देखकर संतोष हुआ कि स्कूलों में काम और आगे बढ़ा है। दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के प्रदर्शन में अब कोई अंतर नहीं किया जा सकता। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में ओलंपियन अमन सेहरावत और रवि दहिया के अलावा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज पूरे जोन की सरकारी और निजी स्कूलों की स्पोर्ट्स प्रतिभाएं यहां हैं। मैं इसे खेल प्रतिभा नहीं कहता। बल्कि हमारे बीच आने वाले ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ी हैं। हम भविष्य में इनमें से कुछ बच्चों को टीवी पर देखेंगे और गर्व से कहेंगे कि यह बच्चा कभी हमारे साथ जोन 1 में था और आज कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक, एशियाई गेम्स या नेशनल गेम्स में देश का झंडा फहरा रहे हैं। हमें भी गर्व होगा कि कभी ये बच्चे हमारे सामने बैठते थे और हम इनका प्रदर्शन देख रहे थे। कई बच्चे आगे चलकर जिला, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। सभी को भविष्य के लिए बधाई देते हुए कहा कि मुझे यहां आकर बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं लगभग डेढ़ साल से अपने शिक्षा के काम से दूर था। मुझे लग रहा था कि इन डेढ़ सालों में यह कार्यक्रम कितने आगे बढ़े होंगे। कहीं, पिछले 10 सालों में मेरे किए गए काम पीछे तो नहीं हो गए। लेकिन आपके बीच में आकर लगा कि नहीं, यह पीछे नहीं हुआ, बल्कि और आगे बढ़ा

उन्होंने बताया कि स्कूल लेवल पर स्पोर्ट्स की पढ़ाई का एक और अहम योगदान है। मैं चाहूंगा कि इस पर हमारे शिक्षकों को बच्चों से बात करनी चाहिए। हम बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित करते समय एक गलती करते हैं और कहते हैं कि जिनके अंदर अच्छा स्पोर्ट्स है, वे ऊपर आएं। मुझे लगता है कि हर बच्चे को हर स्पोर्ट्स में भाग लेना बहुत जरूरी है। यह उस बच्चे के लिए भी जरूरी है जो आईएस या आईपीएस, टीचर, अधिकारी, कंपनी का मालिक, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। स्कूल लेवल पर हर बच्चे को स्पोर्ट्स में भाग लेना जरूरी है। इसलिए भी कि उसमें से कोई चैंपियन निकलेगा और इसलिए भी कि भविष्य में देश को जो आईएस, आईपीएस, बिजनेस मैन या प्राइवेट कंपनी का सीईओ मिलेगा, कम से कम जब वह 40-50 साल का होगा, तो उसे अपने घुटनों की देखभाल के लिए किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उन्होंने कहा कि अगर हम स्पोर्ट्स के लिए काम करेंगे तो अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस जोन में जितने बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चे खेल के मैदान में चैंपियन बनेंगे, वहीं कुछ बच्चे बिजनेस और कुछ राजनीति के क्षेत्र में चैंपियन बनेंगे। कोई वकील बनेगा तो कोई पत्रकार बनेगा। आप वहां के चैंपियन बनेंगे। लेकिन वहां भी आपकी चैंपियनशिप में सबसे बड़ी बाधा आपकी सेहत होगी। मैं 50 साल का हो चुका हूं, तो मुझे इसका अनुभव है। उन्होंने कहा कि जिस तरह छोटे-छोटे बच्चे यहां प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें देखकर मुझे लगता है कि अगर मुझे भी बचपन में ये सब कराया होता, तो आज मुझे भी घुटनों में दर्द की शिकायत नहीं होती। मुझे घुटनों को ठीक रखने के लिए अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग यह नहीं कह पाते हैं। आप सभी खिलाड़ियों में से कौन खेल, नौकरी, या बिजनेस के क्षेत्र में चैंपियन बनेगा, यह आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। लेकिन जब मैंने आपको यहां आगे बढ़ते हुए देखा, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से हर कोई भविष्य में अपनी-अपनी जिंदगी का चैंपियन बनेगा।

उन्होने बताया कि आजकल जब मैं लोगों के बीच घूमता हूं, तो देखता हूं कि हर तीसरी गली में एक जिम या बॉडी फिटनेस सेंटर खुला हुआ है। इन फिटनेस सेंटर्स और जिम में सबसे ज्यादा उन्हें जाने की जरूरत पड़ती है जो लोग अपने स्कूल के दिनों में खेल पर ध्यान नहीं देते। मैं चाहूंगा कि खेल अथॉरिटी देश को अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी देने की जिम्मेदारी लें। साथ ही, यह भी जिम्मेदारी लें कि जो लोग देश के अन्य क्षेत्रों में जाएंगे, वे भी फिट और हष्ट-पुष्ट रहेंगे। यह जिम्मेदारी भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी को ही लेनी होगी।

राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन : देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जननायक, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करके भाजपा मुख्यालय का घेराव किया। जब प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के साथ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे, पुलिस ने आगे नही जाने दिया और उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गए, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जिला, ब्लाक, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल, एनएसयूआई, सेल एवं विभागों के चेयरमैन, पदाधिकारी भी मौजूद थे।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा शीर्ष नेतृत्व द्वारा उकसाये जाने के उपरांत भाजपा नेताओं द्वारा उन्हें जान से मारने, उन्हें आतंकवादी कहना और जुबान काटने जैसी तीखी बोली के बाद मैं भाजपा नेताओं की मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या हम इनकी भाषा में जवाब नहीं दे सकते परंतु यह कांग्रेस की परम्परा, संस्कृति, विचारधारा और परवरिश नहीं है कि हम भी वही भाषा बोलें जो भाजपा के लोग अपनी जुबान से जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर इस तरह के बयान और चेतावनी देने वालों पर गृह मंत्रालय खुद कार्यवाही करें।

उन्होने बताया कि कन्यायकुमारी से कश्मीर तक हजारों किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, बारिश से नही डरे। यहां तक की आतंकवादियों ने उन्हें उड़ाने की धमकी दी, तब भी राहुल गांधी नही डरे। तब भाजपा प्रहार करके राहुल गांधी को डराने की कोशिश क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा नेता अमित शाह यह सोच रहे है कि हमारे नेता राहुल गांधी पर प्रहार करने से हम डर जाऐंगे।

उन्होंने बताया कि भाजपा क्या सोचती है, वह क्यों राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रही है? क्या राहुल गांधी का दोष यह है कि वो देश के करोड़ों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों की आवाज बनकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे है। भाजपा इसलिए राहुल गांधी को रोकना चाहती है कि वे मजबूत संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे है, संविधान बचाने की लड़ाई में राहुल जी देश की जनता के साथ खड़े है।

उन्होने बताया कि भाजपा को मैं बता देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी तक पहुँचने के लिए देश के लाखों करोड़ कांग्रेस और राहुल जी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले शुभचिंतकों के उपर से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी भाजपा राहुल गांधी पर आंख और उंगली उठाने की हिमाकत कर पाऐगी। मुझे गर्व है कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जो मजबूती के साथ राहुल जी की दीवार बनकर अपनी कर्तव्यनिष्ठा के साथ यहां आऐ है।

उन्होंने बताया कि देश के करोड़ो महिलाओं, बुर्जुगों, युवाओ, दलितों, पिछड़ो के अधिकारों की रक्षा के लिए तानाशाह भाजपा को जवाब देने का वक्त आ गया है। हमारी लड़ाई लम्बी है, हमें मजबूती के साथ मिलकर देश और देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी है।

खुशी फाउंडेशन ने पूर्ण विधि विधान से किया श्री गणेश विसर्जन

नई दिल्ली। दिल्ली के अंबेडकर नगर स्थित खानपुर हरिजन कैंप में श्री गणपति जी 7 तारीख से 17 तारीख तक गणपति जी बिठा गए थे गणपति जी का पूर्ण विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। अगले बरस जल्दी आने की कामना के साथ श्री गणेश जी को सभी ने विदाई दी। अतिथि के तौर पर खुशी फाऊंडेशन चैरिटेबल सोसायटी की अध्यक्ष गीता यादव जी उपाध्यक्ष आशीष मैसी जी और एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष महरौली भाजपा चंद्रपाल बैरवा जी शामिल रहे। सहयोगियों में हरिजन कैंप की टीम आकाश करोटिया गुलशन करोटिया सूरज नदीम फैजान सनी राहुल विशाल आदि इन सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा गणपति जी के विसर्जन का कार्यक्रम सफल रहा।

दिल्लीवालों को सोचना है कि केजरीवाल सीएम नहीं होंगे तो योजना का क्या होगा?: संजय सिंह

सुषमा रानी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सभी सरकारी सुविधाओं का त्याग करने का फैसला किया है। इसकी जानकारी देते हुए ''आप'' के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास को छोडकर अब आम लोगों की तरह रहेंगे। उनकी सुरक्षा को खतरा है। पहले उन पर कई बार हमले हो चुके हैं। फिर भी उन्होंने सरकारी सुरक्षा छोड़ने का फैसला किया है। अब दिल्लीवालों को सोचना है कि केजरीवाल सीएम नहीं होंगे तो दिल्ली में मिल रही मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की बस यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थयात्रा योजना का क्या होगा? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि मुफ्त सुविधाएं बंद होनी चाहिए और भाजपा दिल्लीवालों को मुफ्तखोर कह कर बदनाम करती है। भाजपा दिल्लीवालों को मिल रही तमाम मुफ्त सुविधाएं बंद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल देश के इकलौते नेता हैं, जो अपनी ईमानदारी पर वोट मांग रहे हैं और हमें पूरा भरोसा कि वह जनता की अदालत से प्रचंड बहुमत से अपनी ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद संजय सिंह ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस फैसले से दिल्ली की जनता बहुत दुखी और गुस्से में हैं कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए अनेकों काम किए। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी? केजरीवाल ने तो बड़ी ईमानदारी से दिल्ली के दो करोड़ लोगों की सेवा की। ऐसे में उनको इस्तीफा देने की कोई जरूरत ही नहीं थी।

संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली और देश के लोग देख रहे हैं कि पिछले दो साल से भाजपा लगातार अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे आरोप खड़े किए, जबकि एक रुपए का अभी तक सबूत नहीं मिला है। भाजपा वालों ने केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कहा और उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े किए। कोई आम नेता या मोटी चमड़ी वाला नेता होता तो उसे भ्रष्टाचार के इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी कुर्सी से चिपका रहता। लेकिन यह अरविंद केजरीवाल हैं। केजरीवाल ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से यहां तक का सफर तय किया और ईमानदारी से दिल्लीवालों की सेवा की है।

उन्होंने कहा कि जिस पीएमएलए के मामले में जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है, उसमें अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया। कोई और नेता होता तो वह कहता कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे जमानत मिल गई है, काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई, ईडी ने राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई की है। सीबीआई ने पिंजरें में बंद तोते की तरह काम किया है। कोई और नेता होता तो कहता कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुना दिया है, अब अपने पद पर बना रहूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तय किया कि हम जनता की अदालत में जाएंगे। पिछले 10 सालों में जिस जनता की हमने ईमानदारी से सेवा की है, हम उससे ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी व्यक्ति बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, अरविंद केजरीवाल को भी वह सारी सुविधाएं मिलीं। मंगलवार को इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल ने तय किया कि मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं वह छोड़ देंगे। बाकी नेताओं को भी हमने देखा है कि अगर वह किसी पद पर पहुंच गए और सुविधा मिल गई तो पद छोड़ने के बाद भी उन सुविधाओं को पाने के लिए सालों तक लड़ाई लड़ते हैं। सरकारी आवास से चिपके रहते हैं, लेकिन केजरीवाल ने अपना सरकारी आवास खाली करने का फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल 15 दिन के अंदर सरकारी आवास खाली कर देंगे।

उन्होने बताया कि कि यहां सवाल अरविंद केजरीवाल का नहीं, बल्कि दिल्ली की दो करोड़ जनता का है। अरविंद केजरीवाल के साल भाजपा जो कर रही है, वह पूरी दिल्ली देख रही है। केजरीवाल के साथ, उनके शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन जनता के आशीर्वाद और अपने हौसले से अरविंद केजरीवाल ने भाजपा की गंदी राजनीति को जबाब देने का काम किया। अब समय दिल्ली के लोगों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश को मुफ्त की सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। सारी मुफ्त की सुविधाए बंद हो जानी चाहिए। अब दिल्ली की जनता को सोचना है कि अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे तो दिल्ली के लोगों का क्या होगा?

उन्होने बताया कि अब दिल्ली के लोगों को तय करना है, संकल्प लेना है और जवाब देना है। अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि जनता की अदालत से प्रचंड बहुमत से अपनी ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। अरविंद केरीवाल हिन्दुस्तान के इतिहास में पहले नेता हैं, जो सीना ठोक कर कह रहे हैं कि ईमानदार हूं तो वोट देना, ईमानदार नहीं हूं तो वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर वोट मांग रहे हैं। अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब दिल्ली के दो करोड़ लोगों का वक्त है। इस समय दिल्ली के दो करोड़ लोगों पर जिम्मेदारी है कि वह भाजपा के साजिशों और कुचक्रों का जवाब अपने वोट की ताकत से देंगे।

राहुल गांधी पर टिप्पणी कर फंस सकते हैं केंद्रीय मंत्री बिट्टू, हाईकोर्ट में कार्रवाई के लिए याचिका दायर

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिट्टू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि बिट्टू की टिप्पणी से वह व्यथित हैं और उन्होंने बिट्टू के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हिंदू सेना अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने याचिका दायर कर कहा कि वह बिट्टू की टिप्पणी की से व्यथित हैं।

सुरजीत यादव ने राहुल के विरुद्ध अपमानजनक, भ्रामक और झूठे बयानों के लिए शिकायत दर्ज करने के साथ-साथ बिट्टू के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है।

याचिका में क्या कहा गया

याचिका के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी भारतीय नहीं हैं, उन्होंने अपना अधिकांश समय बाहर बिताया है। वह अपने देश से ज्यादा प्यार नहीं करते, क्योंकि वह विदेश जाते हैं और हर बात गलत तरीके से कहते हैं। मोस्ट वांटेड, अलगाववादियों और बम, बंदूक और गोले बनाने में माहिर लोगों ने राहुल गांधी की बात की सराहना की है। अगर नंबर वन आतंकवादी और देश के सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ने का पुरस्कार होना चाहिए तो वह राहुल गांधी को मिलना चाहिए।

मंत्री की टिप्पणी भड़काने वाली

सुरजीत यादव ने याचिका में तर्क दिया कि केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियां न केवल निराधार हैं, बल्कि नफरत और हिंसा को भी भड़काती हैं। इसके कारण देश के कई हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

राहुल गांधी को बताया है आतंकी

यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी में उन्हें देश का दुश्मन और आतंकवादी बताया गया है, जिसका बहुआयामी और महत्वपूर्ण प्रभाव है। ये टिप्पणियां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ा सकती है और संसदीय सत्रों और सार्वजनिक बहसों में टकराव बढ़ सकता है।

दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी, गाजियाबाद में बनेगा नया एम्स; सीएम योगी ने किया ऐलान

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर के आसपास रहने वाले लोगों से जुड़ी बड़ी खबर है। अब बीमार पड़ने पर इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अब गाजियाबाद शहर में नया एम्स खुलेगा। इस बात की घोषणा आज प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक दिवसीय दौरे के दौरान कही। इसके अलावा सीएम ने विपक्ष पर प्रहार किया। पढ़ें योगी ने अपने भाषण में क्या-क्या बातें कहीं।

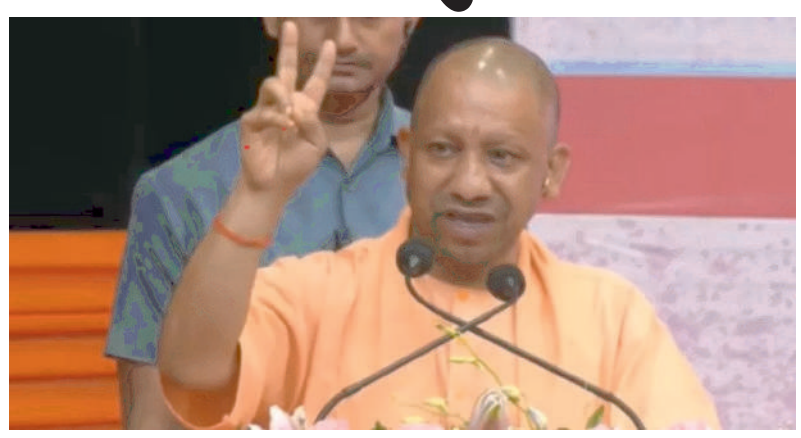

गाजियाबाद। गाजियाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एम्स जैसा सेंटर बनेगा। इसकी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जल्द ही सेंटर का निर्माण कार्य कराया जाएगा। यह बड़ी घोषणा बुधवार को मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कही है।

सीएम ने कहा कि आज गाजियाबाद कितना बदल गया है। पहले यहां क्या स्थिति थी। एक तरफ पावन दूधेश्वर नाथ मन्दिर है तो दूसरी तरफ यहां पर गंदगी, माफिया की पैरलल सरकार और गुंडागर्दी थी। सात साल पहले जो लोग गाजियाबाद आये थे, वह अब आएंगे तो इसे पहचान नहीं आ पाएंगे।

गाजियाबाद बन चुका स्मार्ट सिटी- सीएम योगी

यहां पर 14 लेन का एक्सप्रेस-वे बना है। देश की पहले नमो भारत ट्रेन का परिचालन यहां हो रहा है। यहां पर मेट्रो सेवा, एयरपोर्ट सेवा भी उपलब्ध है। सुरक्षा का बेहतरीन माहौल है।

आज गाजियाबाद स्मार्ट सिटी बन चुका है। यहां कन्वेंशन सेंटर के मॉडल के रूप में पूर्वांचल भवन, उत्तरांचल भवन बन रहे हैं। दूधेश्वर नाथ मन्दिर के पास सफाई व्यवस्था बेहतर है।

अगले तीन साल में बनाना है नंबर एक- योगी आदित्यनाथ

पिछले साढ़े सात साल में जो विकास कार्य हुआ है, उससे उत्तर प्रदेश अब देश मे नम्बर एक अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन गया है। सपा के समय यह सातवें नम्बर पर था। अगले तीन साल में इसे नम्बर एक पर लाना है।

इस दौरान सीएम ने कहा कि मैंने पूछा था कि मौसम कैसा है? पहले सुनील शर्मा, फिर अतुल गर्ग से पूछा, दोनों ने कहा कि मौसम कैसा भी आपको सुनने के लिए सब उत्सुक हैं। इसलिए मैं आपके बीच मे आया हूँ।

'यूपी से अब माफिया गायब'

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ अब निकलती है। माफिया गायब हो गए हैं। इससे इनको संरक्षण देने वालों की नींद उड़ी है। वह अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं।

कांग्रेस और सपा को आस्था न युवा की चिंता है, परिवार की चिंता है। जातिवाद के नाम पर आपस मे लड़ाने का काम करेंगे, दंगाइयों को छूट देंगे। दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, इनके संबंध सपा से हैं। सपा आज दरिंदों का गैंग बन चुकी है।

हद है! 7 गुना तक बढ़ाया टैक्स, गाजियाबाद में जमकर शुरू हुआ विरोध; व्यापारी बोले- यह हिटलरशाही है

परिवहन विशेष न्यूज

यूपी के गाजियाबाद में नगर निगम द्वारा टैक्स बढ़ाने का विरोध शुरू हो गया है। व्यापारियों ने सोशल मीडिया पर भी विरोध करना शुरू कर दिया है। साथ ही व्यापारियों ने कहा कि यह सीधे-सीधे हिटलरशाही है। उधर नगर निगम के पूर्व मेयर ने भी बढ़े टैक्स के विरोध में तल्ख प्रतिक्रिया की है। पढ़िए व्यापारियों ने और क्या-क्या कहा है।

गाजियाबाद। गाजियाबाद में नगर निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयों पर तीन से सात गुना टैक्स बढ़ाने का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व मेयर अशु वर्मा ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नगरवासियों का हित सर्वप्रथम। एक साथ इतना टैक्स नहीं बढ़ा सकते। बढ़े टैक्स का जमकर विरोध हो।

नगर निगम की ओर से औद्योगिक इकाइयों व व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर तीन से सात गुना तक टैक्स बढ़ा दिया गया है। उद्यमियों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने इतना अधिक टैक्स बढ़ाए जाने को लेकर उद्यमी से लेकर व्यापारी तक गुस्से में है।

उनका कहना है कि सुविधाओं के नाम पर औद्योगिक क्षेत्रों में नगर निगम की ओर से कोई मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती। सड़कें टूटी हैं और जलनिकासी न होने से जलभराव होता है और पेयजल तक की व्यवस्था नहीं है। टैक्स किस वजह से बढ़ाकर वसूलने की मंशा है। वहीं, नगर निगम के पूर्व मेयर ने भी बढ़े टैक्स के विरोध में तल्ख प्रतिक्रिया की है।

औद्योगिक क्षेत्र में इकाइयों के कवर्ड एरिया पर नगर निगम की ओर से टैक्स वसूला जाता था, पर अब ओपन एरिया में भी टैक्स लगा दिया गया। मेरठ रोड की इकाइयों पर एक लाख रुपये की जगह सात लाख रुपये टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस भेजा है। - हंसपाल प्रीतम सिंह, उद्यमी, मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र

हम अपने शहरवासी, व्यापारी व उद्यमी को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा लुटते नहीं देख सकते। इसका विरोध हर पार्षद व आमजन को करना होगा। यह सीधे-सीधे हिटलरशाही है। इसके लिए महापौर से भी संज्ञान लेकर इसे पूर्ववत करने का आग्रह किया है। - ***अशु वर्मा, पूर्व मेयर, नगर निगम***

हमारे यहां औद्योगिक इकाइयों पर 22 हजार रुपये का टैक्स नगर निगम को जाता था, पर इस बार इसे बढ़ाकर करीब 70 हजार कर दिया गया है। हमें पिछले वर्ष का टैक्स जोड़कर करीब सवा लाख रुपये का नोटिस निगम से आया है। - ***मोहित कुशाल, उद्यमी, एसएसजीटी रोड औद्योगिक***

यीडा की नई योजना, प्राधिकरण को मिले पांच आवेदन; ऐसे किया जाएगा भूखंडों का आवंटन

यीडा यमुना प्राधिकरण (यीडा) एक नई योजना लेकर आया है। इस योजना के लिए पांच आवेदकों ने आवेदन किया लेकिन निर्धारित मानक पूरा न करने के कारण दो को रद्द कर दिया गया। यीडा द्वारा यह योजना विश्वविद्यालयों के लिए निकाली गई है। वहीं आयोजकों के साक्षात्कार के बाद भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। योजना के बारे में आगे विस्तार से पढ़िए।

ग्रेटर नोएडा। यीडा तीन विश्वविद्यालय यमुना प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों के लिए निकाली गई भूखंड योजना में तीन आवेदकों ने पात्रता की शर्तों को पूरा किया है। दो आवेदन निर्धारित मानक पूरा न करने के कारण रद्द हो गए। अगले सप्ताह सोमवार को साक्षात्कार के माध्यम से इन आवेदकों को भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।

इसके साथ ही प्राधिकरण विश्वविद्यालय के लिए दस भूखंड की एक और योजना निकालने जा रहा है। यमुना प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय के लिए पांच भूखंड की योजना निकाली थी। इस योजना में प्राधिकरण को पांच आवेदन मिले हैं।

गठित समिति ने आवेदकों की पात्रता की जांच की

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने मंगलवार को आवेदकों की पात्रता की जांच की। इसमें एमिटी विश्वविद्यालय, आचार्य कुंद-कुंद एजूकेशन सोसायटी, डॉ. अखिलेश दास, महात्मा गांधी मिशन, दरबारी लाल फाउंडेशन के आवेदन की जांच की गई।

इसमें एमिटी, महात्मा गांधी मिशन, आचार्य कुंद कुंद एजूकेशन सोसायटी के आवेदन शर्तों पर खरा उतरे। डॉ. अखिलेश दास व दरबारी लाल फाउंडेशन के आवेदन को रद्द कर दिया गया। पांचों भूखंड सेक्टर 22 ई में हैं।

दस भूखंडों की नई योजना निकाली जाएगी

डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि अगले सप्ताह आयोजकों के साक्षात्कार के बाद भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। अगले सप्ताह विश्वविद्यालय के लिए दस भूखंडों की नई योजना निकाली जाएगी। पांच भूखंड सेक्टर 17 व पांच सेक्टर 22 ई में है।

नीलगाय के आने से बिदका खच्चर, मिट्टी से भरी बुग्गी पलटने से दबकर पिता-पुत्र की मौत

परिवहन विशेष न्यूज

पिता और बेटे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। दोनों जंगल से मिटी लेने गए थे और बुग्गी से लौट रहे थे। खच्चर के सामने नीलगाय आने से वह बिदक गया और बुग्गी पलट गई। बेटे की गर्दन पर पहिया चढ़ गया और पिता बुग्गी के नीचे दब गया। मदद नहीं मिलने से दोनों की मौत हो गई।

गाजियाबाद। टीला मोड़ थाना क्षेत्र के निस्तौली गांव में बुधवार तड़के जंगल से बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेकर लौट रहे पिता और पुत्र की बुग्गी में जुड़ा खच्चर नीलगाय का झुंड देखकर बिदक गया। इससे मिट्टी से भरी बुग्गी पलट गई। हादसे में बुग्गी के नीचे दबकर पिता पुत्र की मौत हो गई।

सुबह राहगीर ने देखा तो घटना की जानकारी हुई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो स्वजन से कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। गमगीन माहौल में गांव में ही दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

बर्तन बनाने के लिए गए थे मिट्टे लेने

पुलिस के अनुसार, निस्तौली गांव में 42 वर्षीय दिनेश पत्नी और दो बेटे प्रियांशु और दीपांशु के साथ रहते थे। वह मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बुधवार तड़के चार बजे वह खच्चर जोड़कर बुग्गी से बेटे प्रियांशु (18) के साथ जंगल में डंपर से डलवाई गई मिट्टी लाने गए थे। लौटते समेत रास्ते में खच्चर के आगे नीलगाय का झुंड आ गया।

बुग्गी पलटने से दब गए दोनों

नीलगाय देखकर खच्चर बिदक गया। सड़क से नीचे मिट्टी में उतर गया। इस दौरान बुग्गी पलट गई। सुबह करीब आठ बजे राहगीर वहां से गुजर रहे थे तो बुग्गी पलटी देखी। आसपास के लोगों को जानकारी दी। लोगों मौके पर पहुंचे और बुग्गी को सीधा किया तो दिनेश

बुग्गी के नीचे मिट्टी में दबे हुए थे और प्रियांशु की गर्दन पर पहिया चढ़ गया था।

लोगों ने स्वजन को सूचना दी। जानकारी मिलने पर टीला मोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ले जानी लगी। स्वजन और ग्रामीणों ने हादसा बताकर कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया।

मदद मिलती तो बच सकती थी दिनेश की जान

मृतक दिनेश के चाचा डॉ. सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह तड़के चार बजे हादसा हुआ। इस दौरान मौके पर कोई नहीं था। प्रियांशु के गर्दन पर मिट्टी से भरी बुग्गी का पहिया चढ़ गया था। जबकि दिनेश बुग्गी पलटने से उसके नीचे दब गए थे। यदि समय से मदद मिल जाती तो दिनेश की जान बच सकती थी। वह घर में इकलौता कमाने वाला था। बर्तन बनाकर परिवार का भरण पोषण कर रहा था।

गांव में किया गया अंतिम संस्कार

चाचा सुरेंद्र सिंह बताया कि दिनेश छह भाई थे। वह तीसरे नंबर पर थे। जबकि उनका बड़ा बेटा प्रियांशु 12वीं कक्षा का छात्र था। दिल्ली स्कूल में पढ़ रहा था।पढ़ लिखकर वह घर की आर्थिक स्थित ठीक करने में मदद करता, लेकिन हादसे में पिता पुत्र दोनों की जान ले ली। घटना से पूरा परिवार सदमे में है। गांव के ही श्मशान घाट में दोनों का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।

नीलगाय खच्चर के सामने से हादसा हुआ।जिसमें पिता और पुत्र की मौत हो गई। स्वजन ने पोस्टमॉर्टम के लिए मना कर दिया। शव स्वजन को सौंप दिया गया। -सलोनी अग्रवाल, सहायक पुलिस आयुक्त, शालीमार गार्डन।

IT इंजीनियर ने आर्मी में तैनात दोस्त संग रची अपहरण की झूठी कहानी, पुलिस ने तीन आरोपी दबोचे

नोएडा में एक्सप्रेस-वे थाना क्षेत्र के सेक्टर-134 में जेपी कॉसमॉस के आईटी इंजीनियर शुभम गौड़ का कथित अपहरण और फिरौती मांगने का मामला फर्जी निकला। इंजीनियर ने आर्मी में तैनात दोस्त ऊधो संग मिलकर अपहरण की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने आर्मी में तैनात दोस्त और युवक समेत तीन को गिरफ्तार किया। पुलिस दो अन्य की तलाश कर रही है।

नोएडा। एक्सप्रेस-वे थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर-134 में जेपी कॉसमॉस के आईटी इंजीनियर शुभम गौड़ का मेवाती गिरोह द्वारा अपहरण करने और 50 लाख रुपये फिरौती मांगने की घटना झूठी निकली। इंजीनियर ने आर्मी में तैनात दोस्त ऊधो संग मिलकर अपहरण की झूठी कहानी रची थी। स्वजन को बेटे के मोबाइल से ही फोन से फिरौती की रकम घटाते जाने, घर-परिवार और रिश्तेदारों की संपति की अंदरूनी जानकारी होने पर शक हुआ। इंजीनियर के कॉल डिटेल और सर्विलांस से आरोपियों के फर्जी प्लान की पोल खुल गई। पुलिस ने आर्मी में तैनात दोस्त और युवक समेत तीन को गिरफ्तार किया। दो अन्य की तलाश की जा रही।

पुलिस ने गुमशुदगी की दर्ज की थी शिकायत

एसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि 10 सितंबर रात साढ़े नौ बजे शुभम गौड़ की बिना बताए कहीं चले जाने को लेकर थाना एक्सप्रेस-वे में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। शुभम के मोबाइल से ही कॉल कर छोड़ने की एवज में 50 लाख रुपये की मांग की गई। स्वजन ने इतनी रकम होने से इनकार किया तो आरोपियों ने संपति बेचने को बोला।

शुभम के पिता ने बाद चलना बताया तो आरोपियों ने शुभम के चाचा रियल स्टेट कारोबारी से रुपये उधार लेने को बोला। इस पर स्वजन को शक हो गया और पुलिस को भी बताया।

'एक देश एक चुनाव' अमृतकाल की अमृत उपलब्धि बने

ललित गर्ग

निश्चय ही 'एक देश एक चुनाव' की योजना को लागू करना राजग के लिये बड़ी चुनौती होगी क्योंकि इस बार विपक्ष पहले के मुकाबले मजबूत भी है और एकजुट भी है। इसमें दो राय नहीं कि यह बात तार्किक है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव का प्रयास शासन में सुनिश्चितता लाएगा।

नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने 'एक देश एक चुनाव' के अपने चुनौतीपूर्ण संकल्प को लागू करने की बात कहकर राजनीतिक चर्चा को गरमा दिया है। भारत के लोकतंत्र की मजबूती एवं चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रासंगिक एवं कम खर्चीला बनाने के लिये 'एक देश एक चुनाव' पर चर्चा होती रही है। इसको लेकर भाजपा जिस तरह बेझिझक होकर तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा कि केंद्र को सहयोगी दलों का पूरा समर्थन मिल रहा। दो बड़े दलों में से एक जेडीयू ने मोदी के 'एक देश एक चुनाव' वाले इरादे पर सहमति जता दी है। कहा गया कि राजग सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल के भीतर इस महत्वपूर्ण चुनाव सुधार को लागू कराने को लेकर आशावादी है और उसके इस आशावाद में देश को एक नई दिशा मिल सकेगी। भारत की वर्तमान चुनावी प्रणाली में निहित कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा एक संभावित समाधान के रूप में उभरी है। शासन के सभी स्तरों- पंचायत, नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय- में एक साथ चुनाव कराने से लागत (खर्च)-प्रभावशीलता और प्रशासनिक दक्षता से लेकर बेहतर शासन और नीति निरंतरता तक कई लाभ मिल सकते हैं। यह नये भारत, सशक्त भारत एवं विकसित भारत के संकल्प को आकार देने का मुख्य आधार बन सकता है एवं आजादी के अमृतकाल की एक अमृत उपलब्धि बनकर सामने आ सकता है।

भले ही स्पष्ट बहुमत के अभाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग की तीसरी पारी में बदलावकारी फैसले लेना उतना सहज नहीं रह गया है, जितना पहली-दूसरी पारी में नजर आता था। लेकिन भाजपा की सरकार इतनी भी कमजोर नहीं है कि अपने चुनावी वायदों एवं विकासमूलक कार्ययोजनाओं को लागू न कर सके। नरेन्द्र मोदी जैसा साहसी एवं करिश्माई नेतृत्व है तो उसके द्वारा देशहित की योजनाओं में आने वाले अवरोध वह दूर कर ही लेंगे। एक दशक की विकासमूलक कार्यशैली के बाद अब भी भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर अपनी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। भले ही भाजपा-सरकार कई मुद्दों पर यू टर्न लेते हुए भी नजर आई। बहरहाल, लोकसभा में पहले के मुकाबले कमजोर स्थिति होने के बावजूद खुद को साहसिक निर्णय लेने वाली पार्टी के रूप में एक बार फिर अपने एक मुख्य एजेंडे 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को आकार देने के लिये तत्पर हो गयी है। इसके लिए सरकार ने पक्ष-विपक्ष के सभी नेताओं से एक साथ आने का अनुरोध किया था। निस्संदेह, एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिये भाजपा द्वारा नई पहल किए जाने के निहितार्थ राजनीति से ज्यादा राष्ट्रहित में है।

निश्चय ही 'एक देश एक चुनाव' की योजना को लागू करना राजग के लिये बड़ी चुनौती होगी क्योंकि इस बार विपक्ष पहले के मुकाबले मजबूत भी है और एकजुट भी है। इसमें दो राय नहीं कि यह बात तार्किक है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव का प्रयास शासन में सुनिश्चितता लाएगा। वहीं बार-बार के चुनाव खर्चीले होते हैं। दूसरे राज्य-दर-राज्य लंबी

आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य भी बाधित होते हैं। साथ ही साथ शासन-प्रशासन व सुरक्षा बलों की ऊर्जा के क्षय के अलावा जनशक्ति का अनावश्यक व्यय होता है। विगत लोकसभा चुनावों में कुल सरकारी खर्च 6600 करोड़ रुपये आया था जो भारत जैसे विविधतापूर्ण विशाल देश को देखते हुए भले ही जायज कहा जाये, लेकिन बार-बार होने वाले चुनावों से होने वाले ऐसे भारी-भरकम खर्चे देश की अर्थ-व्यवस्था पर बोझ तो डालते ही है। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ भी महंगी होती चुनाव व्यवस्था है क्योंकि जब करोड़ों रुपये खर्च करके कोई विधानसभा या लोकसभा का प्रत्याशी जनप्रतिनिधि बनेगा तो वह विजयी होने के बाद सबसे पहले अपने भारी खर्च की भरपाई करने की कोशिश करेगा। अतः असल में बात सम्पूर्ण चुनावी व्यवस्था के सुधार की होनी चाहिए। मगर इसकी बात करने पर सभी राजनैतिक दलों में एक सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन पक्ष एवं विपक्ष को अपने राजनीतिक हितों की बजाय देशहित को सामने रखकर इस मुद्दे पर आम सहमति बनानी चाहिए। पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव के लिये एक साथ चुनावी मशीनरी तथा सुरक्षा बलों की उपलब्धता के यक्ष प्रश्न को भी सामने रखकर इस पर सकारात्मक रूख अपनाना चाहिए और इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत हमेशा से राजनीतिक विचारधाराओं, विविध संस्कृतियों और विशाल आबादी का मिश्रण रहा है। हर गुजरते चुनाव चक्र के साथ, राष्ट्र लोकतांत्रिक उत्साह का महाकुंभ देखता है, जहाँ लाखों लोग अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हालाँकि, इस जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच, विभिन्न स्तरों- स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय-पर चुनावों के समन्वय को लेकर बहस ने हाल के वर्षों में काफी जोर पकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक दशक के शासन एवं पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से किए गए अपने संबोधन में 'एक देश, एक चुनाव' की जोरदार वकालत की थी और कहा था कि बार-बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने राजनीतिक दलों से लाल किले से और राष्ट्रीय तिरंगे को साक्षी मानकर राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा जारी चुनाव घोषणापत्र में उसने 'एक देश, एक चुनाव' को प्रमुख वादों के रूप में शामिल किया था।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने इस साल मार्च में पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। समिति ने राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के साथ परामर्श किया और संभावित अनुशंसाओं के साथ आम लोगो एवं न्यायविदों के विचार आमंत्रित किये। समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की भी सिफारिश की। इसके अलावा, विधि आयोग भी 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। असल में बात सम्पूर्ण चुनावी व्यवस्था के सुधार की होनी चाहिए। मगर इसकी बात करते हुए सभी राजनैतिक दलों के सामने निजी हित एवं चुनाव जीतने का गणित सामने आ जाता है। भारत की असली विडम्बना यही है। जब भी सरकारी खर्चे से चुनाव कराने की बात होती है तो इस राह को अव्यावहारिक बता दिया जाता है। जबकि जर्मनी जैसे लोकतन्त्र में यह प्रणाली सफलतापूर्वक काम कर रही है। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव एक साथ प्रत्येक पाँच वर्ष पर आयोजित किये जाते हैं, जबकि नगर निकाय चुनाव प्रत्येक दो वर्ष पर आयोजित किये जाते हैं। स्वीडन में राष्ट्रीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल/काउंटी कौंसिल और स्थानीय निकायों/नगर निकाय सभाओं के चुनाव एक निश्चित तिथि, यानी हर चौथे वर्ष सितंबर के दूसरे रविवार को आयोजित किये जाते हैं। ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता एवं पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करने के लिये निश्चित अवधि संसद अधिनियम, 2011 पारित किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया कि प्रथम चुनाव 7 मई 2015 को और उसके बाद हर पाँचवें वर्ष मई माह के पहले गुरुवार को आयोजित किया जाएगा।

जब दुनिया के अनेक देशों में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' की परम्परा सफलतापूर्वक संचालित हो रही है तो भारत में इसे लागू करने में इतने किन्तु-परन्तु क्यों है? देश में इसे लागू करने से सरकार कुछ-कुछ समय बाद चुनावी मोड में रहने के बजाय शासन यानी विकास योजना पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। इससे समय एवं संसाधनों की भी बचत होगी। एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के लिए एक साथ कई मत डालना आसान हो जाएगा। इन सब स्थितियों के साथ-साथ एक साथ चुनाव कराये जाने पर क्षेत्रीय पार्टियों को होने वाले नुकसान एवं अन्य स्थितियों पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि एक आदर्श एवं सशक्त लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों के लिये समान अवसर उपलब्ध होना भी जरूरी है।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

अब हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में भी होंगे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन

परिवहन विशेष न्यूज

भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) और हाउसिंग बोर्ड की नई कॉलोनियों में भी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। इसके लिए शासन ने निर्देश दिए थे। हाउसिंग बोर्ड के तुलसी ग्रीन प्रोजेक्ट में पहले से ही चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था है।

नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने चार साल पहले शहर भर में चार्जिंग स्टेशन बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। अब तक आम जनता के लिए कोई व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई है। जबकि शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

आरईसी ने चौथे री-इन्वेस्ट के दौरान ₹ 1.12 लाख करोड़ के लिए आरई डेवलपर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

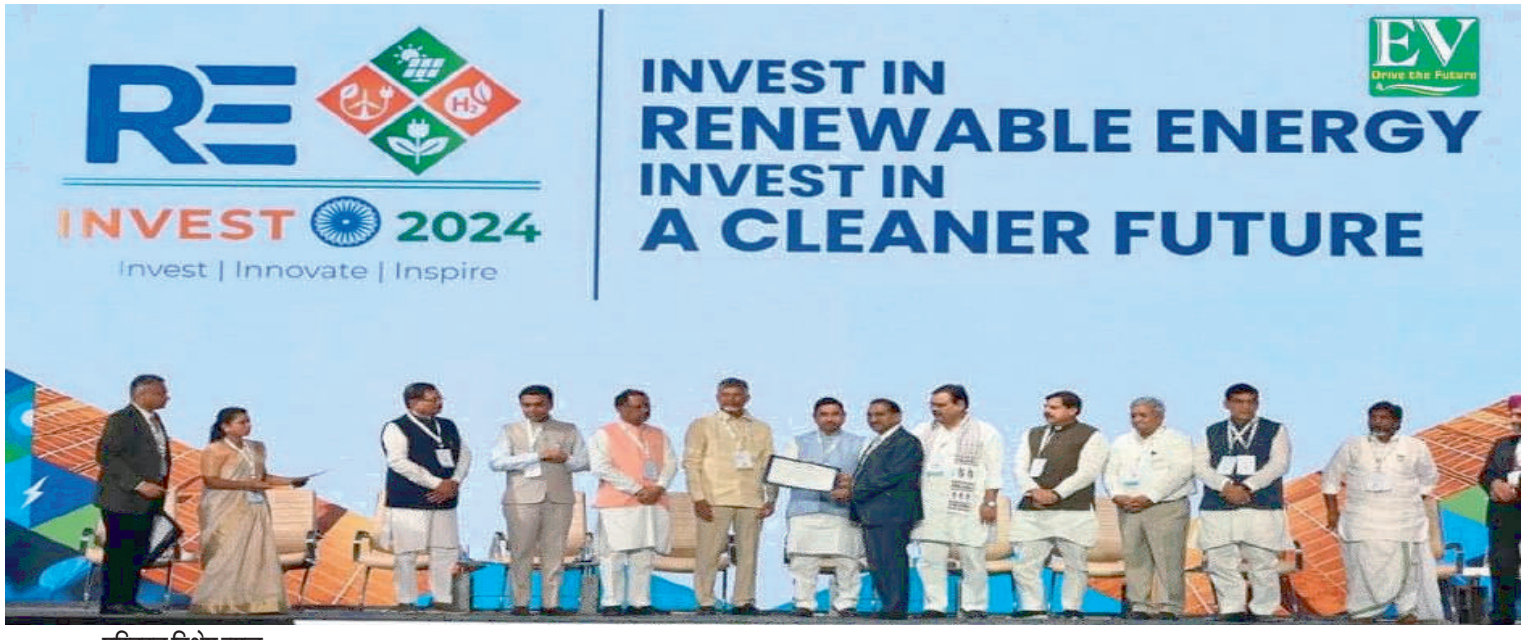

परिवहन विशेष न्यूज

विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसयू और एक प्रमुख एनबीएफसी आरईसी लिमिटेड ने गांधीनगर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो (री-इन्वेस्ट 2024) के दौरान आरई डेवलपर्स के साथ लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा।

समझौता ज्ञापनों में सौर और पवन हाइब्रिड परियोजनाओं, सौर और पवन राउंड द क्लॉक (आरटीसी) परियोजना, फर्म और डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) बिजली, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बेस), पंप स्टोरेज, हाइड्रोपावर, ग्रीन अमोनिया/हाइड्रोजन, सोलर सेल/मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और अन्य अभिनव तकनीकों पर आधारित परियोजनाएं शामिल हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग, ईवी इकोसिस्टम सहित संबंधित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण के लिए भी चर्चा चल रही है। इसके अलावा, आरईसी शीर्ष रेटेड ऑफटेकर वाले सीएंडआई सेगमेंट के लिए डेवलपर्स द्वारा रिन्यूएबल परियोजनाओं पर विचार करने के लिए भी खुला है।

आरईसी ने इस आयोजन में भाग लिया और कई प्रमुख हितधारकों और अग्रणी आरई डेवलपर्स के साथ व्यापारिक चर्चा की। आरईसी की योजना 2030 तक देश की स्थापित गैर जीवाश्म आधारित उत्पादन क्षमता को 200 गीगावाट से 500 गीगावाट तक पहुंचाने की यात्रा में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने का है। आरईसी ने 2030 तक अपनी अक्षय ऊर्जा ऋण पुस्तिका को 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक तक बढ़ाने के लिए 'शपथ पत्र' के माध्यम से वित्तीय प्रतिबद्धता जताई है। इससे 2030 तक अक्षय ऊर्जा का हिस्सा मौजूदा 8% से बढ़कर 30% हो जाएगा, क्योंकि आरईसी की ऋण पुस्तिका 2030 तक 10 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह शपथ पत्र आरईसी के सीएमडी श्री विवेक कुमार देवांगन, आईएएस द्वारा श्री प्रहलाद जोशी, माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कैबिनेट मंत्री को सौंपा गया।

शपथ पत्र सौंपने के बाद आरईसी के सीएमडी ने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गोवा के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 3 लाख करोड़ रुपये के वित्तपोषण की अपनी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता के लिए केन्द्रीय मंत्री से मान्यता प्राप्त की।

अब नए वाहन के लिए ले सकेंगे अपनी पुरानी गाड़ी का नंबर

परिवहन विशेष न्यूज

राजस्थान में अब अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर स्क्रैप किए पुराने वाहन का पंजीयन क्रमांक (रजिस्ट्रेशन नंबर) नए वाहन को आवंटित किया जा सकेगा। परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर रिटेंशन की सुविधा को वाहन स्क्रैप करवाए जाने पर प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी।

राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के तहत अब वाहन स्वामी अपने पूर्व के वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर को नए खरीदे गए वाहन पर रिटेन कर सकेंगे। इस संबंध में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किए।

परिवहन व सड़क सुरक्षा आयुक्त मनीषा अरोड़ा ने बताया कि बजट घोषणा के अनुसार अब वाहन मालिक अपने पूर्व के पंजीकृत वाहन पंजीयन क्रमांक को नए खरीदे वाहन पर रिटेन कर सकते हैं। इस संबंध में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि कोई भी आवेदक वी स्क्रैप पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। वाहन को अधिकृत स्क्रैप सेंटर को देकर पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट दिया जाएगा। स्क्रैप करने के बाद सर्टिफिकेट आफ व्हीकल स्क्रेपिंग जारी किया जाएगा।

इसके बाद वाहन मालिक संबंधित पंजीयन अधिकारी को पंजीयन क्रमांक रिटेंशन की निर्धारित फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। स्क्रैप हुए वाहन के पंजीयन क्रमांक को नए क्रय किए जाने वाले वाहन पर लेने के लिए पोर्टल पर अनुमत किए जाने की सूचना वाहन मालिक को एसएमएस या सिटिजन पोर्टल के माध्यम से मिलेगी।

टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक वाहनों की पुनर्विक्रय और विनिमय मूल्य बढ़ाने की योजना, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रयुक्त कार बाजार में पायलट परियोजना शुरू की

परिवहन विशेष न्यूज

देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) मालिकों को रीसेल और एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करने के लिए पुरानी कारों के बाजार के साथ काम करना शुरू कर दिया है। कंपनी के प्रवक्ता ने मीडिया को बताया 'हम उन मालिकों को ईवी की रीसेल/एक्सचेंज सुविधा प्रदान करने के अवसरों पर काम कर रहे हैं, जो नई ईवी अपनाना चाहते हैं। फिलहाल हमारी योजनाएं शुरुआती चरण में हैं और हम पुरानी कारों के ऑनलाइन बाजार के साथ छोटे स्तर पर प्रायोगिक शुरुआत कर रहे हैं।'

कंपनी के पास भारत में ईवी के लिए सबसे ज्यादा जगह है, जो अनुमानित रूप से करीब 1,70,000 वाहनों के लिए है पर्याप्त है। प्रायोगिक शुरुआत के तौर पर कंपनी पहले ही पुरानी कारों के ऑनलाइन बाजार स्पिनी के साथ काम शुरू कर चुकी है। हालांकि टाटा मोटर्स और स्पिनी दोनों ने ही इस विषय में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर पुरानी टाटा नेक्सॉन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

मुंबई में 2021 का नेक्सॉन ईवी एक्सजेड प्लस मॉडल इस प्लेटफॉर्म पर 11.61 लाख रुपये में उपलब्ध है। नई टाटा नेक्सन ईवी 12.49 लाख रुपये से लेकर 16.49 लाख रुपये के बीच उपलब्ध है।

डीलरशिप के सूत्रों ने कहा कि आम तौर पर ईवी के दाम उनके तेल-गैस इंजन वाले मॉडलों के अनुरूप कम होते हैं। पहले साल में यह कमी लगभग 25 प्रतिशत होती है और उसके बाद दामों में यह कमी उस वाहन के इस्तेमाल (तय की दूरी और बैटरी लाइफ) पर निर्भर करती है।

टाटा मोटर्स के प्रवक्ता ने कहा कि पुराने ईवी का बाजार तीन से चार साल के अंतराल के साथ नए ईवी बाजार के काफी करीब होने के संभावना है। प्रवक्ता ने कहा, 'पुराने ईवी का बाजार तीन से चार साल के अंतराल के साथ नए ईवी बाजार के काफी करीब होने के आसार हैं, क्योंकि शुरुआत में इन्हें अपनाने वाले लोग लंबी दूरी तथा और ज्यादा आधुनिक ईवी में अपग्रेड करते हैं। ईवी की बड़ी मात्रा साल 2021-22 की है और इसलिए हम अपग्रेड करने वालों की शुरुआती खेप 12 से 24 महीने में देखेंगे।'

टाटा मोटर्स के मुंबई के दो डीलरों ने इस बात की पुष्टि की कि उन्हें पहले ही ऐसे ग्राहक नजर आने लगे हैं, जो टाटा की नई ईवी के लिए टियागो या नेक्सन ईवी को एक्सचेंज करना चाहते हैं।

मुंबई के पूर्वी उपनगर के एक डीलर ने कहा 'एक्सचेंज की मांग आने पर हम अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अगर कंपनी पुरानी ईवी खरीदने वाले बाजार के साथ गठजोड़ करती है, तो यह बहुत अच्छा होगा क्योंकि इस श्रेणी में दर का मानक स्तर चुनौती बनी हुई है।'

पुरानी कारों के बाजार के एक अधिकारी ने कहा कि इस बाजार से खरीदने का फायदा यह है कि इस पुरानी ईवी पर वारंटी होगी।

रिवोल्ट आरवी1 इलेक्ट्रिक बाइक भारत में हुई लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल क्षेत्र में अपने वाहन पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए रिवोल्ट मोटर्स ने भारत में अपनी तीसरी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आरवी1 लॉन्च की है। ई-मोटरसाइकिल अब रिवोल्ट के लाइनअप में सबसे किफायती मॉडल है जिसमें आरवी400 और आरवी400 BRZ शामिल हैं।

डिजाइन की बात करें तो रिवोल्ट ने उपयोगिता और व्यावहारिकता पर जोर देते हुए आरवी1 के लिए एक सरल स्ट्रीट बाइक डिजाइन का विकल्प चुना है। सामने से शुरू करते हुए आरवी1 में एक गोलाकार एलईडी हेडलैंप और एक स्मोक्ड विंडस्क्रीन और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 6 इंच का डिजिटल एलसीडी डिस्प्ले है। मोटरसाइकिल बिल्ट-इन चार्जर स्टोरेज के साथ आती है। रिवोल्ट के अनुसार आरवी1, सेगमेंट में सबसे लंबी सीट और 250 किलोग्राम की पेलोड ले जाने की क्षमता है।

पावरट्रेन के लिए आरवी1 दो वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें मानक वैरिएंट 2.2 kWh बैटरी मिलता है जो 100 किमी तक की रेंज देता है और आरवी1+ में एक बड़ा 3.24 kWh

बैटरी पैक है जो पूर्ण रूप से 160 किमी की रेंज का वादा करती है। दोनों बैटरी पैक 2kW इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आते हैं जो आरवी400 पर बेल्ट ड्राइव के विपरीत, चेन ड्राइव के माध्यम से पीछे के पहिये तक ताकत पहुंचाते हैं। आरवी1+ फास्ट-चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और 1.5 घंटे में फुल चार्ज करने में सक्षम है। रिवोल्ट ने आरवी1 को रिवर्स मोड के साथ भी पेश किया है ताकि ई-मोटरसाइकिल को तंग पार्किंग स्थानों में ले जाना आसान हो सके। साइकिल पार्ट्स के लिए आरवी1 में एक टेलीस्कोपिक फोर्क और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सेटअप मिलता है, जबकि ब्रेकिंग को दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक द्वारा कंट्रोल किया जाता है।

रिवोल्ट आरवी1 के लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए रतनइंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड की चेयरपर्सन श्रीमती अंजलि रतन ने कहा, "स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाने की हमारी खोज जो बजट के अनुकूल हो, जो कि गुणवत्ता, फीचर्स या सुरक्षा से समझौता न करती हो। आधुनिक और बदले हुए लुक और सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ फीचर्स के साथ आरवी1 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में स्टाइल और व्यावहारिकता का एक नया स्तर लाती है। अत्याधुनिक तकनीक और विचारशील डिजाइन का एक आदर्श मिश्रण, आरवी1 को समझदार भारतीय सवारों के लिए एक रोमांचक सवारी अनुभव देने के लिए बनाया गया है।कीमत में 40,000 रुपये तक की कटौती की है, जिसके बाद अब इस इलेक्ट्रिक हैचबैक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत महज 7.99 लाख रुपये हो गई है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका में किया दावा, कुछ सालों में भारत बन जाएगा 'वैश्विक ऊर्जा का पावरहाउस'

परिवहन विशेष न्यूज

(सीमा हाकू काचरू) ह्यूस्टन (अमेरिका): ऊर्जा के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हरदीप पुरी ने दुनिया की ऊर्जा जरूरतों पर चर्चा के लिए अमेरिका में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि अगले दो दशकों में भारत वैश्विक ऊर्जा मांग में 25 फीसदी का योगदान देगा यानी दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भारत अकेले 25 फीसदी का योगदान देगा। एक तरह से भारत वैश्विक ऊर्जा का पावरहाउस बन जाएगा।

यहां जॉर्ज आर.ब्राउन कन्वेंशन सेंटर में 52वीं गैसटेक एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस भारत सहित विश्व के पांच प्रमुख ऊर्जा मंत्रियों की रणनीतिक अंतर्दृष्टि के साथ मंगलवार, 17 सितंबर को शुरू हुई। 'दृष्टिकोण, नवाचार और कार्रवाई के जरिये ऊर्जा में बदलाव' विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में वैश्विक ऊर्जा स्थिरता तथा तेजी से कार्बन मुक्त बनने की आवश्यकता पर गौर किया गया। अपने मुख्य भाषण में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में भारत की बढ़ती प्रभावशाली भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, '' यदि वैश्विक मांग एक प्रतिशत

बढ़ रही है, तो हमारी मांग तीन गुना तेजी से बढ़ रही है।

अगले दो दशकों में भारत ऊर्जा मांग में वैश्विक वृद्धि में 25 प्रतिशत का योगदान देगा।'' मंत्री ने भारत की चुनौती को ''ऊर्जा त्रिविधता'' के रूप में पेश किया और उपलब्धता, सामर्थ्य तथा सफल हरित बदलाव के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

पुरी ने कहा, '' हमें हरित बदलाव को प्रबंधित करने और इसमें सफलता प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है।'' सम्मेलन की पहली मंत्रिस्तरीय समिति में अमेरिका, भारत, मिस्र, नाइजीरिया और तुर्किये के अधिकारी शामिल रहे। इन्होंने महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक और उद्योग चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। इस बीच, भारत और अमेरिका ने न्यायसंगत तथा व्यवस्थित ऊर्जा बदलाव के लिए ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा संसाधन के लिए सहायक विदेश मंत्री ज्योफ्री प्याट से यहां मुलाकात की। पुरी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''.आज ह्यूस्टन में मेरे मित्र और अमेरिका के ऊर्जा संसाधन के लिए सहायक विदेश मंत्री ज्योफ्री प्याट से मुलाकात की। हमने मौजूदा ऊर्जा सहयोग की समीक्षा की और एक न्यायसंगत तथा व्यवस्थित ऊर्जा बदलाव के लिए ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की।'' प्याट ने भी सोशल मीडिया पर पुरी से मुलाकात और दोनों देशों के बीच बनी सहमति की जानकारी दी।

नीट युजी 2025: मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका, केंद्रित और शांत रहने की रणनीतियाँ

विजय गर्ग

नीट युजी की तैयारी के दौरान संयम, एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के कुछ मूल तरीके यहां दिए गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य के प्रभावों को पहचानना परीक्षा की तैयारी मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर है। परीक्षा प्रदर्शन, स्मृति प्रतिधारण और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सभी तनाव, चिंता और जलन से दृढ़ता से प्रभावित हो सकती हैं। अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य के परिणामस्वरूप ध्यान में कमी, नींद चक्र में गड़बड़ी और ड्राइव की अनुपस्थिति हो सकती है।

प्रभावी नीट युजी तैयारी के लिए केवल शिक्षाविदों से अधिक की आवश्यकता होती है; तनाव को प्रबंधित करने और फोकस बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस, नियमित व्यायाम और संतुलित जीवनशैली को शामिल करना आवश्यक है। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एनईईटी की तैयारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने और ध्यान केंद्रित करने के लिए टिप्स, जिसमें माइंडफुलनेस और तनाव प्रबंधन रणनीतियाँ शामिल हैं। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा स्नातक (एनईईटी यूजी) की तैयारी प्रक्रिया मांगलिक और तनावपूर्ण हो सकती है। एक कठिन अध्ययन कार्यक्रम को प्रबंधित करने के लिए सिर्फ अकादमिक तैयारी से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है और अच्छी तरह से हासिल करने के लिए दबाव भी होता है - मजबूत मानसिक स्वास्थ्य उपाय भी आवश्यक हैं। केंद्रित शिक्षण, सफल अध्ययन और सामान्य प्रदर्शन के लिए मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना आवश्यक है। नीट युजी की तैयारी के दौरान संयम, एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के कुछ मूल तरीके यहां दिए गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य के प्रभावों को पहचानना परीक्षा की तैयारी मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर है। परीक्षा प्रदर्शन, स्मृति प्रतिधारण और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सभी तनाव, चिंता और जलन से दृढ़ता से प्रभावित हो सकती हैं। अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य के परिणामस्वरूप ध्यान में कमी, नींद चक्र में गड़बड़ी और ड्राइव की अनुपस्थिति हो सकती है। परिणामस्वरूप, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय उपाय करने से सफल अध्ययन और एनईईटी यूजी प्रदर्शन की आपकी क्षमता में सुधार हो सकता है। तनाव प्रबंधन और फोकस बनाए रखने की तकनीकें 1. माइंडफुलनेस तकनीकों को शामिल करें: माइंडफुल होने में बिना कोई निर्णय लिए यहीं और अभी पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। योग, ध्यान या गहरी साँस लेने के व्यायाम जैसे माइंडफुलनेस अभ्यासों को शामिल करने से तनाव और चिंता के प्रबंधन में सहायता मिल सकती है। प्रतिदिन केवल दस से पंद्रह मिनट के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से फोकस और भावनात्मक विनियमन में मदद मिलेगी, जो आपको एनईईटी की तैयारी की मांगों से बेहतर ढंग से

निपटने में मदद कर सकता है। 2. प्राप्य लक्ष्य बनाएं और छोटी जीत को स्वीकार करें: प्राप्य लक्ष्य रखने से प्रेरणा और सफलता की भावना बनाए रखने में मदद मिलती है। अपनी तैयारी को प्रबंधनीय लक्ष्यों में विभाजित करें, जैसे किसी अध्याय को पूरा करना या किसी निश्चित विषय पर विशेषज्ञ बनना। अपने सुधार को पहचानें, अपने आप को एक छोटे से उपहार से पुरस्कृत करें, या इन छोटी सफलताओं का जश्न मनाने के लिए एक सुखदायक गतिविधि में संलग्न हों। यह विधि आपकी प्रेरणा बनाए रखती है और सकारात्मक आचरण को पुरस्कृत करती है। 3. एक अनुकूलित अध्ययन योजना स्थापित करें: एक सख्त, सभी के लिए उपयुक्त अध्ययन कार्यक्रम को संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय, एक अनुकूलित अध्ययन योजना बनाएं जो आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या और सीखने की शैली के साथ काम करे। अध्ययन सत्रों को सुपाच्य भागों में विभाजित करें और संक्षिप्त ब्रेक शामिल करें। अपने कौशल और कमियों के अनुसार विषयों को प्राथमिकता सूचियों में क्रमबद्ध करें, और सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सत्र में प्राप्य लक्ष्य हों। लचीला शेड्यूल होने से आपको तनाव से निपटने और अपनी आवश्यकताओं में बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलती है 4. नियमित रूप से व्यायाम करें: व्यायाम तनाव कम करने की एक उत्कृष्ट रणनीति है। नियमित व्यायाम से एंडोर्फिन का उत्पादन होता है, जो जैविक मूड बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार के व्यायाम के उदाहरणों में जॉगिंग, साइकिल चलाना या यहां तक कि तेज चलना भी शामिल है। व्यायाम ऊर्जा और सामान्य स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है, जो अध्ययन सत्र के दौरान एकाग्रता को सुविधाजनक बनाता है। सप्ताह के अधिकांश दिनों में, कम से कम 30 मिनट व्यायाम करने का प्रयास करें। 5. संतुलित आहार और पर्याप्त जलयोजन रखें- इष्टतम मानसिक और शारीरिक प्रदर्शन के लिए, संतुलित आहार और पर्याप्त जलयोजन पूर्वापेक्षाएँ हैं। संपूर्ण रूप से समृद्ध आहार तैयार करेंअनाज, दुबला प्रोटीन, फल और सब्जियाँ। मीठे स्नैक्स और बहुत अधिक कॉफी से बचना चाहिए क्योंकि ये ऊर्जा में कमी और बढ़ी हुई चिंता का कारण बन सकते हैं। पानी आपको हाइड्रेटेड रखता है और आपको ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। 6. विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें: विश्राम कौशल प्राप्त करने से चिंता कम होगी और आपको आराम करने में मदद मिलेगी। जो तकनीकें अच्छी तरह से काम करती हैं उनमें प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम, निर्देशित कल्पना और आरामदायक संगीत शामिल हैं। अपने दिमाग को स्पष्ट और एकाग्र रखने के लिए, इन प्रथाओं को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करें, खासकर अध्ययन सत्र या सोने से पहले। 7. आराम और नींद को प्राथमिकता दें- स्वस्थ मस्तिष्क विकास और सामान्य भलाई के लिए पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि आप लगातार सोने के शेड्यूल का पालन करें और हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लें। देर रात तक पढ़ाई करने और सोने से ठीक पहले स्क्रीन का उपयोग करने से दूर रहें क्योंकि ये आपकी नींद में बाधा डाल सकते हैं। पर्याप्त नींद लेने वाला दिमाग अधिक एकाग्र, जागृत और परीक्षा के तनाव को संभालने में सक्षम होता है। नीट युजी की तैयारी को सफल बनाने के लिए प्रभावी मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन आवश्यक है। आप माइंडफुलनेस तकनीकों को लागू करके, प्राप्य उद्देश्य बनाकर, व्यायाम करके और संतुलित जीवनशैली अपनाकर फोकस बढ़ा सकते हैं, तनाव का स्तर कम कर सकते हैं और समग्र रूप से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। याद रखें कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए केवल योजना चरण पूरा करने से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। एनईईटी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शांत, एकाग्र और तैयार रहने के लिए इन तकनीकों को अभ्यास में लाएं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट

संपादकीय

अंतत: देश की जनगणना

भारत की नई, ताजा और अद्यतन जनगणना की शुरुआत होने वाली है। केंद्र सरकार शीघ्र ही औपचारिक घोषणा करेगी और पूरा कार्यक्रम देश के सामने रखेगी। 2011 की जनगणना के बाद अब यह कवायद की जाएगी। नियम रहा है कि हर 10 साल के बाद जनगणना कराई जाएगी, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के कारण 2021 की जनगणना नहीं की जा सकी। अब भारत दुनिया के उन तीन देशों में एक है, जहां नई जनगणना का सम्यक कार्यक्रम अभी घोषित किया जाना है। ऐसा 'यूएन पॉपुलेशन फंड' के 'ग्लोबल सेंसस ट्रैरकर' का दावा है। बेशक कोरोना ने वैश्विक स्तर पर लगभग सभी देशों को खूब प्रभावित किया, नतीजतन वे जनगणना समेत कई अभियान नहीं चला पाए, लेकिन उन्होंने महामारी से उबर कर जनगणना के अपने कार्यक्रम भी घोषित किए और जनगणना की प्रक्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं। भारत भी 2021 के अंत तक आते-आते कोरोना से लगभग मुक्त हो चुका था, लेकिन जनगणना की शुरुआत क्यों नहीं की गई, इसका सटीक जवाब भारत सरकार ही दे सकती है। चूंकि भारत में जनगणना नहीं हो सकी, लिहाजा नया डाटा प्राप्त नहीं है, नतीजतन 'जातीय जनगणना' का राजनीतिक नेरेटिव सामने आया है। हालांकि दोनों में तुलना नहीं की जा सकती। वैसे भी राज्य जनगणना के लिए अधिकृत नहीं है। यह दायित्व केंद्र सरकार का ही है। बहरहाल अब जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो उसे डिजिटल तरीके से भी किया जाए। नागरिकों को स्व-गणना और स्व-सत्यापन का अधिकार दिया जाए और जनगणना का परंपरागत तरीका भी इस्तेमाल किया जाए। इससे डाटा स्पष्ट, सुगम और यथाशीघ्र उपलब्ध होगा और क्रॉस चेकिंग भी की जा सकेगी। हालांकि जनगणना का अधिकृत फैसला लिया जा चुका है, लेकिन अब भी तय नहीं है कि उसका डाटा कब तक सार्वजनिक रूप से जारी किया जाएगा। अतीत में जनगणना के प्रथम चरण के सम्पन्न होने में ही करीब 11 माह का वक्त लगा था। भारत में जनगणना की प्रक्रिया बेहद जटिल, पेचीदा और व्यापक है, क्योंकि राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र 35 से अधिक हैं और कुल आबादी 145 करोड़ को छू रही होगी! बहरहाल नई, ताजा जनगणना बेहद जरूरी है, क्योंकि वह ही सभी आकलन, विश्लेषण और सर्वेक्षणों की कसौटी है।

अभी तक हम 2011 की जनगणना की गिरफ्त में हैं। यदि उसी के आधार पर भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करना है, तो निष्कर्ष गलत आएगा। बीते 13 सालों में भारत बिल्कुल बदल चुका है। आज वह विश्व की महाशक्तियों में शामिल है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2011 की जनगणना के पुराने डाटा के भरोसे ही स्वास्थ्य, जनसंख्या और आर्थिकी के डाटा भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। यही नहीं, एनएसएसओ समेत अन्य एजेंसियों के सर्वेक्षणों की गुणवत्ता भी गलत साबित हुई है। एक उदाहरण ही पर्याप्त है। यह अनुमान है कि करीब 11 करोड़ भारतीयों को 'खाद्य सुरक्षा कानून' के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि 2011 की जनगणना के तहत लाभार्थियों की संख्या तब भी गिनी जा रही थी। संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन भी जनगणना पर ही आधारित है। परिसीमन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। संसद ने 'महिला आरक्षण बिल' पारित किया था, लेकिन वह तभी लागू किया जा सकेगा, जब परिसीमन हो जाएगा और संसद की सीटें बढ़ा दी जाएंगी। परिसीमन तभी होगा, जब जनगणना के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध होंगे। 'जातीय जनगणना' का मुद्दा भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने 2024 के आम चुनाव में, कुछ राज्यों में, मतदान को प्रभावित किया था। जाति के साथ आरक्षण भी जुड़ा है। सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर यह मुद्दा शांत नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर साल औसतन 70-80 लाख युवा भारतीय श्रम-बाजार में आते हैं। हमें निजी क्षेत्र में भी रोजगार मुहैया कराने की जरूरत है, ताकि यह संकट कम होता जाए। उसके मद्देनजर केंद्र सरकार को 'जातीय जनगणना' के प्रति भी 'खुला' होना पड़ेगा और अपने रुख में बदलाव लाना होगा। बहरहाल जनगणना की अच्छी, सुखद खबर आई है, तो उसका स्वागत है, लेकिन अब सरकार को किसी बहाने की आड़ में छिप कर जनगणना को टालना नहीं चाहिए। सच्चाई यह है कि हमारे पास भावी योजनाएं बनाने के लिए किसी तरह का डाटा उपलब्ध नहीं था।

कहां खो गईं पीड़ा समझने वाली भावनाएं

एक मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता दे दिया तो राजनीति और धर्म के ठेकेदार इतने तड़पे कि संसद में उस कानून को बदलना पड़ा, पर देश की बेटियां कानूनी छाया में देह व्यापार करें, न कोई तड़पा, न प्रदर्शन हुए, न कोई मशाल मार्च। कौन नहीं जानता कि बीस करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। कौन नहीं जानता कि सडक़ों पर बच्चे जन्म लेते और वहीं आधे बूढ़े होकर मर जाते हैं। लाखों बच्चे लापता हैं। वे फंसाए गए होंगे या देह व्यापार में या अंगों की तस्करी में या अपराधों की दुनिया में। मेरा तो अपने देश के नेताओं से, धर्म गुरुओं से, मानवाधिकारियों से एक ही सवाल है कि ये भावनाएं तभी क्यों घायल होती हैं जब केवल धर्म के तथाकथित ठेकेदार लोगों को, समाज को भडक़ाते हैं

अपने देश में और कहीं-कहीं दुनिया में भी एक शब्द वाक्य यदा-कदा सुनने को मिलता है- भावनाएं आहत हो गईं, धार्मिक भावनाओं का अपमान कर दिया। कुछ स्थानीय भाषाओं में यह भी कह दिया कि हृदय वलूंदरे गए अर्थात हृदय पर गहरी चोट की गई। यह चोट भावों और भावनाओं की रहती है। कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो केवल पूजा स्थानों या विशेष संप्रदाय के महापुरुषों से जुड़ी रहती हैं। अगर वही भावनाएं अनियंत्रित हो जाएं तो फिर न किसी का सिर काटने में संकोच होता है, न आग लगाने में, न दंगा करने में और न ही विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलने में संकोच किया जाता है। मेरा साधारण और स्वाभाविक प्रश्न यह है कि यही संवेदना या आक्रोश की भावनाएं दया या विरोध की भावनाएं उस समय क्यों छिपी रहती हैं, सोई रहती हैं, जब मानवता के विरुद्ध बहुत बड़ा अपराध होता है। जब बच्चे जन्म लेते ही बिना इलाज के मौत के मुंह में चले जाते हैं और सरकारें केवल नवजात शिशुओं की मृत्यु के आंकड़े देकर ही अपने कत्र्तव्य की इतिश्री समझ लेती हैं। हिंदुस्तान जैसे देश में आज तक असंख्य बेटियां जन्म से पहले मां के गर्भ में ही क्रूरता से कत्ल कर दी गईं या नवजात बच्चियां कूड़े के ढेर पर फेंक दी गईं जहां बहुत बार कुत्तों ने उन्हें नोंच-नोंच कर खा लिया। उस समय वे भावनाएं न जाने किस गड्ढे में दबी रहती हैं जो भावनाएं किसी का सिर कटवा देती हैं, आग लगवा देती हैं, हत्याएं करने में भी कोई संकोच नहीं करतीं। इस समय सुरसा के मुंह की तरह जो भयावह संकट देश के सामने है, आकाश से बरस रहा है, कहीं भयानक बारिश के रूप में, कहीं बादल फटने के रूप में और जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों की आंखें बरस रही हैं, हजारों लोग प्रतिवर्ष इसी बाढ़ और बादलों के कहर के कारण मौत के मुंह में चले जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, उनके लिए आम जन से लेकर नेताओं तक की भावनाएं बिल्कुल शांत हो चुकी हैं।

आमजन तो बेचारा आमजन है। रोटी-रोजी के लिए संघर्ष करता हुआ कि जिंदगी एडियां रगड़-रगड़ कर जी लेता है, पर जो देश के बड़े बड़े नेता, शासक राजनीति के स्वामी हैं वे भी बाढ़ की समस्या को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे जितना उनको लेना चाहिए। कटु सत्य यह है कि दुनिया में बाढ़ से जितनी जन-धन की हानि होती है, उसका बीस प्रतिशत केवल भारत में है। हर वर्ष वर्षा होती है, आगे भी होती रहेगी, पर आज तक यह प्रबंध क्यों नहीं हो पाया कि जो क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होते ही हैं, उन क्षेत्रों से जनता को हटाकर कहीं दूर बसा दिया जाए। यह प्रयास भी नहीं हुआ कि नदियों-दरियाओं के रास्ते में जो अवैध कब्जे और अवैध खनन के कारण बाढ़ की स्थिति बनती है, उसे ही नियंत्रित कर लिया जाए। श्री केदारनाथ धाम में 12 वर्ष पहले जो कुदरत का कोप आदमी को सहना पड़ा, उसके लिए भी यही कारण बताया गया है/था कि जिन क्षेत्रों में पानी को बहना है उसी जमीन पर कब्जा करके बड़े-बड़े भवन खड़े किए गए, जिसके कारण यह कोप अधिक भयानक हो गया। आसाम की बाढ़ कौन नहीं जानता। अभी मॉनसून पूर्व की वर्षा का ही आगमन होता है तो वहां बाढ़ शुरू हो जाती है। इस समय तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे बहुत से प्रांतों में वर्षा से बाढ़ बन चुके कुदरती कोप का भयानक रूप देखने को मिल रहा है। क्या यह सच नहीं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अनेक लोग बाढ़ के कारण मौत के मुंह में जा चुके हैं। अभी कुछ दिन ऐसे समाचार आगे भी मिलते रहेंगे, पर प्रश्न फिर वही है कि एक साधारण से चित्र या शब्द या किसी की टिप्पणी से जो क्रोध, आक्रोश, हिंसा और बदले की भावना देश को जलाने के लिए भडक़ती है, वही भावना अपने देशवासियों को बचाने के लिए क्यों सामने नहीं आती? वर्षा हम नहीं रोक सकते, बादल कब फटेंगे नहीं जानते, भूस्खलन और पहाड़ों का गिरना प्रकृति के हाथ में है, पर वहां बसे अपने देशवासियों को सुरक्षित स्थान पर मुसीबत आने से पहले ही ले जाना, यह तो देश के नेताओं के हाथ में है। अपने-अपने धार्मिक स्थलों की विशालता और अपने बड़प्पन का गुणगान करने वाले न धार्मिक नेता, न राजनीति के स्वामी, न जाने क्यों मौन धारण रखते हैं? कहीं उत्तराखंड में बाढ़ में गाडियां बह गईं, कहीं भवन गिरने से लोग दब कर मर गए। गुजरात के 28 जिलों में इस वर्ष बाढ़ का भयानक कहर बरपा। दिल्ली में संसद के अंदर भी पानी पहुंच गया। राजस्थान और दिल्ली की बेसमेंट में पानी में कुछ लोग डूब गए। अभी हाल ही में दिल्ली में एक अंडरपाथ में कार डूबी, साथ ही दो जिंदगियां डूब गईं। न जाने कितना बचपन इसी प्राकृतिक आपदा के कारण जिंदगी से वंचित हो गया।

इसके लिए किसी को तड़पते नहीं देखा। केवल वही तड़पते हैं जिनके परिजन इस प्राकृतिक कोप का शिकार हो गए। एक नहीं अनेक ऐसे प्रसंग हैं, जहां मानव हृदय पीड़ित होना चाहिए। नेताओं की भावनाएं सेवा सहायता के लिए जन-जन तक राहत देने के लिए पहुंचनी चाहिए। और भी देखिए, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन यह निर्णय दे दिया कि लड़कियां देह व्यापार कर सकती हैं अर्थात अपना शरीर किसी वासना लोलुप की वासना पूरी करने के लिए देकर नोट कमा सकती हैं, उस दिन से भी वे सभी गूंगे बने हैं जो साधारण किसी एक कार्टून, किसी एक टिप्पणी या किसी देवी-देवता के चित्र के नाम पर लडऩे-मरने को तैयार हो जाते हैं। देश की बेटियां शरीर बेचकर नोट कमाएं, वह भी कानूनी मान्यता के साथ, किसी की भावनाएं न त्रस्त हैं, न एक भी शब्द उनके मुख से निकला है। इससे पहले जब लिव इन रिलेशन, पुरानी भाषा में यह कहिए तो महिलाओं को रखैल की तरह रखने का कानून जब बना या अवैध संबंधों को मान्यता दी गई, तब भी वे सब गूंगे बने रहे जिनसे आशा थी कि वे इन निर्णयों से तड़पेंगे और इन्हें रद करवाएंगे। एक मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता दे दिया तो राजनीति और धर्म के ठेकेदार इतने तड़पे कि संसद में उस कानून को बदलना पड़ा, पर देश की बेटियां कानूनी छाया में देह व्यापार करें, न कोई तड़पा, न प्रदर्शन हुए, न कोई मशाल मार्च। कौन नहीं जानता कि बीस करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। कौन नहीं जानता कि सडक़ों पर बच्चे जन्म लेते और वहीं आधे बूढ़े होकर मर जाते हैं। लाखों बच्चे लापता हैं। वे फंसाए गए होंगे या देह व्यापार में या अंगों की तस्करी में या अपराधों की दुनिया में। मेरा तो अपने देश के नेताओं से, धर्म गुरुओं से, धर्म के तथाकथित ठेकेदारों से, मानवाधिकारियों से एक ही सवाल है कि ये भावनाएं तभी क्यों घायल होती हैं जब केवल धर्म के तथाकथित ठेकेदार लोगों को भडक़ाते हैं, किसी धर्म विशेष के विरुद्ध अपने समुदाय को हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं। मानवता और मानव की पीड़ा को समझने वाली, समाधान देने वाली भावनाएं कहां खो गई हैं अपने देश और समाज में?

डिजिटल विभाजन को पाटना: कैसे उद्योग साझेदारी ऑनलाइन शिक्षा को बदल रही है

विजय गर्ग

ऐसे युग में जहां डिजिटल साक्षरता पारंपरिक शैक्षणिक ज्ञान जितनी ही महत्वपूर्ण है, ऑनलाइन शिक्षा का परिदृश्य एक भूकंपीय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वे दिन गए जब ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म केवल आभासी वातावरण में कक्षा के अनुभवों को दोहराते थे। आज, दूरदर्शी संस्थान उद्योग के दिग्गजों के साथ शक्तिशाली गठजोड़ बना रहे हैं, दूरस्थ शिक्षा में एक नया प्रतिमान बना रहे हैं जो वास्तविक दुनिया के कौशल प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान से परे जाता है। मानव रचना सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन डिजिटल लर्निंग में यह क्रांति सिर्फ नई तकनीकों को अपनाने के बारे में नहीं है; यह शिक्षा के मूल को पुनः कल्पना करने के बारे में है। उद्योग विशेषज्ञता को सीधे पाठ्यक्रम में एकीकृत करके, ये साझेदारियाँ एक लंबे समय से चली आ रही चिंता का समाधान कर रही हैं: शैक्षणिक शिक्षा और कार्यस्थल आवश्यकताओं के बीच का अंतर। परिणाम एक गतिशील, भविष्य-प्रूफ शैक्षिक मॉडल है जो डिजिटल युग में कैरियर की तैयारी के बारे में हमारी सोच को नया आकार दे रहा है। इस शैक्षिक कायापलट में सबसे आगे मानव रचना सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (एमआरसीडीओई) खड़ा है, जो ऑनलाइन सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए रणनीतिक सहयोग का लाभ उठाने में अग्रणी है। विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक नेताओं के साथ सावधानीपूर्वक तैयार की गई साझेदारी के माध्यम से, एमआरसीडीओई दूरस्थ शिक्षा में नए मानक स्थापित कर रहा है, जो शिक्षार्थियों को शैक्षणिक कठोरता और उद्योग-प्रासंगिक कौशल का एक अद्वितीय मिश्रण प्रदान करता है। ऑनलाइन शिक्षा के भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण मेटा, सिस्को, यूनिटी, एडोब, ऑटोडेस्क, माइक्रोसॉफ्ट, ईएसबी और ऐप्पल जैसे उद्योग के नेताओं के साथ एमआरसीडीओई की साझेदारी अकादमिक संबद्धता से परे है - वे आभासी कक्षा में वास्तविक दुनिया की विशेषज्ञता लाने के लिए डिज़ाइन किए गए सहयोग हैं। प्रत्येक साझेदारी अत्याधुनिक ज्ञान, व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक अनुभवों के साथ पाठ्यक्रम को बढ़ाती है। ऑनलाइन बीसीए और ऑनलाइन एमसीए कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न उद्योगों में शिक्षार्थी और कामकाजी पेशेवर इन अमूल्य सहयोगों से लाभ उठा सकते हैं। टेक-संचालित लर्निंगइंडस्ट्री साझेदारी व्यक्तियों को आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी प्रौद्योगिकियों में उन्नत ज्ञान के साथ सशक्त बनाती है - कौशल जो आज के नौकरी बाजार में तेजी से आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, मेटा के साथ एमआरसीडीओई का सहयोग शिक्षार्थियों को आभासी वास्तविकता (वीआर) और संवर्धित वास्तविकता (एआर) और विभिन्न उद्योगों में उनके अनुप्रयोगों का पता लगाने की अनुमति देता है। सिस्को के साथ साझेदारी व्यक्तियों को नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा की जटिलताओं से परिचित कराती है, जो उन्हें तकनीक के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक में करियर के लिए तैयार

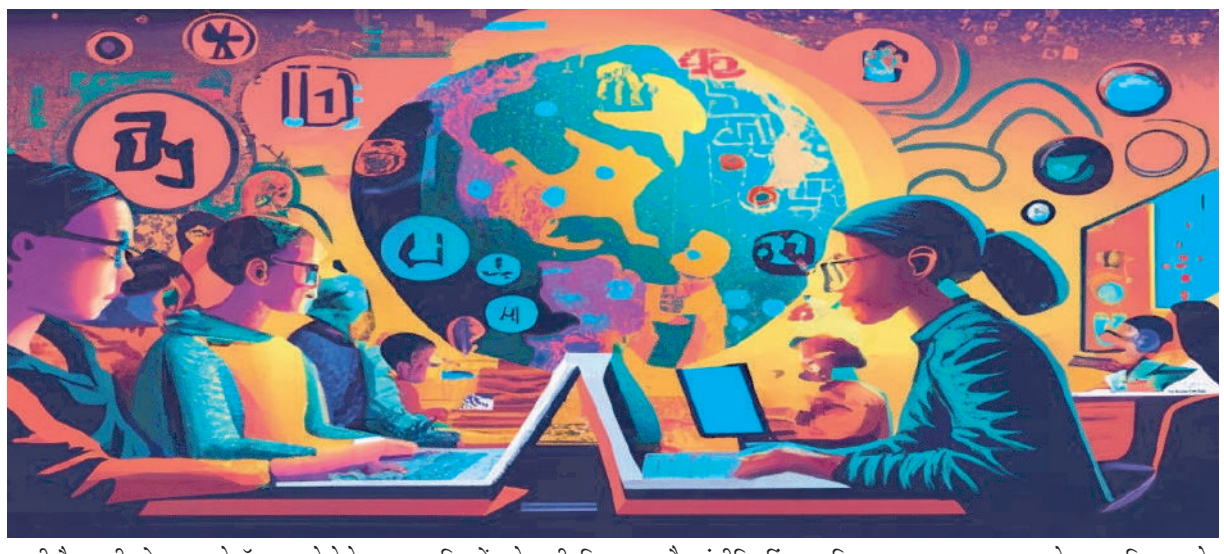

करती है। दूसरी ओर, माइक्रोसॉफ्ट अपने पेशेवर उपकरणों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे छात्रों को ऐसे प्रमाणपत्र प्राप्त करने में मदद मिलती है जो नौकरी बाजार में अत्यधिक मूल्यवान हैं। ऐप्पल की भागीदारी डिजिटल रचनात्मकता और उत्पादकता के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण के साथ पाठ्यक्रम को और समृद्ध बनाती है। क्रिएटिव और डिज़ाइन पार्टनरशिपMRCDOE ग्राफिक डिज़ाइन, एनीमेशन और गेम डेवलपमेंट जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में इच्छुक पेशेवरों को सेवा प्रदान करने के लिए Adobe, AutoDesk और Unity के साथ सहयोग का दावा करता है। ये साझेदारियाँ व्यक्तियों को 3डी डिज़ाइन और इंजीनियरिंग सॉफ़्टवेयर से भी परिचित कराती हैं, जिससे उन्हें परिष्कृत डिज़ाइन और सिमुलेशन बनाने में सशक्त बनाया जाता है। वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रबंधन एमआरसीडीओई में गठबंधन प्रौद्योगिकी और रचनात्मकता से परे व्यापार और वित्तीय प्रबंधन तक फैला हुआ है। एसीसीए (एसोसिएशन ऑफ) के साथ साझेदारी के माध्यम सेचार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स), और हार्वर्ड बिजनेस पब्लिशिंग शिक्षार्थी विश्व स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा और पेशेवर प्रमाणपत्र तक पहुंच प्राप्त करते हैं। एसीसीए शिक्षार्थियों को लेखांकन और वित्त में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता हासिल करने की अनुमति देता है, जिससे बहुराष्ट्रीय निगमों में करियर के द्वार खुल जाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस पब्लिशिंग एमआरसीडीओई छात्रों के लिए एक सर्वांगीण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारे केस स्टडीज, सिमुलेशन, नेतृत्व विकास कार्यक्रम और संकाय विकास सत्र प्रदान करता है। व्यवसाय जगत में अपने करियर को ऊंचा उठाने के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन बीकॉम विद एसीसीए और ऑनलाइन बीबीए/एमबीए कार्यक्रमों के माध्यम से इन सहयोगी अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर को पाटनाएमआरसीडीओई कार्यक्रम एक ही लक्ष्य के साथ डिजाइन किए गए हैं: शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर को पाटना। अपने पाठ्यक्रम को उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़कर, एमआरसीडीओई यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षार्थी न केवल शिक्षित हों बल्कि रोजगार योग्य भी हों। ये साझेदारियाँ छात्रों को उद्योग विशेषज्ञों तक सीधी पहुँच, लाइव परियोजनाओं के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र अर्जित करने के अवसर प्रदान करती हैं। आजीवन सीखने वालों को सशक्त बनाना अग्रणी उद्योग दिग्गजों के साथ सहयोग और साझेदारी विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए एमआरसीडीओई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है जो प्रासंगिक, व्यावहारिक और भविष्योन्मुखी है। पाठ्यक्रम को छात्रों के बीच सीखने की चपलता विकसित करने, उन्हें रोजमर्रा की चुनौतियों के लिए नवीन समाधान खोजने और उद्योग के लिए तैयार होने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन गठबंधनों का लाभ उठाकर, एमआरसीडीओई न केवल आज की नौकरियों के लिए पेशेवरों को तैयार कर रहा है, बल्कि उन्हें भविष्य के उद्योगों में निर्माण और नेतृत्व करने के लिए उपकरणों से भी लैस कर रहा है। इन पहलों के माध्यम से, यह डिजिटल शिक्षा में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करता है, जो रणनीतिक, उद्योग-संचालित शिक्षा के माध्यम से भविष्य को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार

वन नेशन वन इलेक्शन से इकोनॉमी को फायदा या नुकसान, क्या कह रहे एक्सपर्ट?

परिवहन विशेष न्यूज

अलग-अलग चुनाव कराने का विकास दर पर नकारात्मक असर पड़ता है। विशेषज्ञों ने इस बिंदु को समझाने के लिए तमिलनाडु का उदाहरण भी किया है। इसमें बताया है कि वहां 1996 में साथ-साथ चुनाव हुए तो विकास दर में 4.1 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि 2001 में अलग-अलग चुनाव कराने पर 30 प्रतिशत की गिरावट आई। इसी तरह मुद्रास्फीति के लिहाज से भी वन नेशन वन इलेक्शन फायदेमंद दिखा।

नई दिल्ली। देश में लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव से पैसे की बड़ी बचत का पहलू तो स्पष्ट है ही, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का आकलन है कि इससे जीडीपी में लगभग 1.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। वहीं इसके लागू होने पर सरकारें सही मायने में कम से कम साढ़े चार वर्ष विकास कार्य कर पाएंगी। फिलहाल लगातार अलग अलग होने वाले चुनावों और आचार संहिता के कारण सरकारों के हाथ 12-15 महीने तक बंधे होते हैं। यानी पांच साल के लिए चुनी गई सरकार सही मायने में चार साल से कम ही काम करती है।

चुनाव के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर विशेषज्ञ डा. प्राची मिश्रा और उच्च स्तरीय समिति के सदस्य एनके सिंह ने समिति के समक्ष एक शोध प्रस्तुत किया। 'मैक्रोइकोनामिक्स इम्पैक्ट आफ हारमोनाइजिंग इलेक्टोरल साइकल' शीर्षक के इस शोध पत्र में बार-बार होने वाले चुनावों की तुलना में समकालिक यानी एक साथ चुनाव होने की अवधि के दौरान अपेक्षाकृत उच्च आर्थिक वृद्धि, कम मुद्रास्फीति, अधिक निवेश और व्यय का उल्लेख किया गया है। इस अध्ययन में समकालिक चुनाव चक्र के एक या दो वर्ष पहले और बाद की अवधि की तुलना की गई है।

माना गया है कि बार-बार चुनावों के समाज पर और भी अनेक प्रभाव पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर इसके कारण आने वाली अनिश्चितता से सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया बाधित होती है। परियोजनाओं के पूरा होने में देरी होती है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 1952 से 2023 तक प्रतिवर्ष औसतन छह चुनाव हुए। यह आंकड़ा सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के लिए बार-बार होने वाले चुनावों का है। यदि स्थानीय चुनावों को शामिल कर लिया जाए तो प्रतिवर्ष चुनावों की संख्या कई गुणा बढ़ जाएगी।

शोध पत्र में साथ-साथ और अलग-अलग होने वाले चुनावों के पहले और बाद में वास्तविक राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद दर वृद्धि में बदलाव की तुलना की है। दावा किया है कि साथ-साथ चुनावों के बाद वास्तविक जीडीपी वृद्धि अधिक होती है। अलग-अलग चुनावों की तुलना में समकालिक चुनावों के दौरान वास्तविक राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि में लगभग 1.5 प्रतिशत का अंतर देखा गया है।

यह राशि कितनी बड़ी है, इसका आकलन ऐसे कर सकते हैं कि वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत 4.5 लाख करोड़ होता है। यह स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च का आधा और शिक्षा पर होने वाले खर्च का एक तिहाई के बराबर है।

विशेषज्ञों ने इस बिंदु को समझाने के लिए तमिलनाडु का उदाहरण भी किया है। इसमें बताया है कि वहां 1996 में साथ-साथ चुनाव हुए तो विकास दर में 4.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि 2001 में अलग-अलग चुनाव कराने पर 30 प्रतिशत की गिरावट आई। इसी तरह अलग-अलग चुनावों की तुलना में साथ-साथ चुनाव कराने के दौरान मुद्रास्फीति में लगभग एक प्रतिशत की बड़ी गिरावट का अनुमान है।

दीपिका पादुकोण ने खरीदा लग्जरी अपार्टमेंट; जानिए कीमत और लोकेशन समेत पूरी डिटेल

दीपिका पादुकोण की कंपनी KA Enterprises LLP ने नया अपार्टमेंट खरीदा है। दीपिका की सास ने भी वहीं पर अपार्टमेंट खरीदा है। दीपिका के पति रणवीर सिंह पहले से उसी इमारत में कई मंजिलों के मालिक हैं। उन्होंने यह डील 2022 में 119 करोड़ रुपये में की थी। दीपिका और रणवीर हाल ही में एक बच्ची के पैरेंट भी बने हैं।

नई दिल्ली। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण की कंपनी KA Enterprises LLP ने एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है। रियल एस्टेट सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म स्क्वायर याड्र्स के मुताबिक, मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में स्थित यह प्रॉपर्टी 17.78 करोड़ रुपये में खरीदी गई है।

यह प्रीमियम हाउसिंग प्रॉपर्टी प्रतिष्ठित बैंडस्टैंड के पास सागर रेशम को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में है। इस सोसाइटी में प्रीमियम 4 BHK और 5 BHK अपार्टमेंट मिलते हैं। दीपिका के पति और अभिनेता रणवीर सिंह ने पहले से उसी इमारत में कई मंजिलें खरीद रखी हैं। उन्होंने यह डील 2022 में 119 करोड़ रुपये में की थी।

क्या करती है दीपिका पादुकोण की कंपनी

KA Enterprises LLP ग्लोबल वेंचर इन्वेस्टमेंट फर्म है। यह हाई-ग्रोथ कंज्यूमर और कंज्यूमर-टेक कंपनियों पर फोकस करती है। इसका मालिकाना हक दीपिका और उनके पिता प्रकाश पादुकोण के पास है। स्क्वायर याड्र्स के मुताबिक, दीपिका की कंपनी ने जो नया अपार्टमेंट खरीदा है, वो 1,846 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इस डील में लगभग 1.07 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी और 30,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस लगी है। यह सौदा इसी महीने पूरा हुआ है।

दीपिका की सास ने भी खरीदा है अपार्टमेंट

दीपिका की सास अंजू भवनानी ने भी सितंबर में ही 19.13 करोड़ रुपये में एक बगल का अपार्टमेंट खरीदा है। यह भी दिलचस्प बात यह है कि यह डील जिस दिन हुई, उसी दिन अंजू भवनानी का अपार्टमेंट उनकी बेटी रितिका भवनानी और पति जुगजीत सिंह भवनानी को लीज पर दे दिया गया।

लीज की अवधि 55 महीने है। पहले 33 महीनों के लिए मासिक किराया 8.20 लाख रुपये है। वहीं, शेष 22 महीनों के लिए 15 फीसदी बढ़कर 9.43 लाख रुपये हो गया है। 73.80 लाख रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट और 1.29 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी भी समझौते का हिस्सा थी।

हाल ही में मा-पिता बने हैं दीपिका और रणवीर

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हाल ही में पैरेंट बने हैं। दीपिका ने 8 सितंबर को के एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया। दीपिका-रणवीर शादी के 6 साल बाद माता-पिता बने हैं। दीपिका रविवार यानी 15 सितंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुईं। दीपिका मां बनने से पहले 'कल्कि 2898 एडी' फिल्म में नजर आई थीं। इसमें उन्होंने प्रभास और अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन साझा की थी।

6 साल में दोगुनी हो जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था! प्रति व्यक्ति आय का क्या रहेगा हाल?

परिवहन विशेष न्यूज

भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रही है। यह 2030 तक दोगुनी हो सकती है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम का कहना है कि भारत का पहले ही काफी महत्व है और 2047 तक वैश्विक मामलों में इसका और भी अधिक महत्व होगा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए एक मार्ग विकसित करने पर काम कर रहा है।

नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 2030 तक दोगुना हो सकता है। यह बात नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम का। डॉलर के संदर्भ में वर्तमान में भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका आकार 3.7 ट्रिलियन डॉलर है।

सुब्रह्मण्यम ने 'पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया' (पीएएफआई) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जलवायु परिवर्तन भारत के लिए जलवायु प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनने का एक अवसर है। उन्होंने कहा, 'भारत का पहले ही काफी महत्व है और 2047 तक वैश्विक मामलों में इसका और भी अधिक महत्व होगा।'

सुब्रह्मण्यम ने कहा कि 2047 तक भारत जनसांख्यिकी दृष्टि से दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक होगा। वह समृद्धि की ओर अग्रसर होगा और अनुमानित प्रति व्यक्ति आय करीब 18,000 से 20,000 डॉलर होगी। उन्होंने कहा, 'यह वृद्धि महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरने की उम्मीद है, जो पिछले दशक में प्राकृतिक आपदाओं और गरीबी जैसी चुनौतियों से निपटने में की गई पर्याप्त प्रगति पर आधारित है।'

इसके अलावा, सुब्रह्मण्यम ने कहा कि हरित अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है और आयोग 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए एक मार्ग विकसित करने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, 'हमने एक कार्यबल का गठन किया है और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।'

नीति आयोग के सीईओ ने साथ ही कहा कि वैश्वीकरण के लिए सप्लाई चेन में सुधार आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंततः राज्य स्तर पर सुधार तथा सहकारी संघवाद के प्रति प्रतिबद्धता से समावेशी विकास सुनिश्चित होगा, जिससे भारत एक वैश्विक दिग्गज के रूप में उभरेगा और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होगा।

बंद हो रहे कारखाने, बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने का खतरा; क्यों बढ़ रहा संकट?

परिवहन विशेष न्यूज

2021-22 में 18.5 अरब डॉलर से 2023-024 में 14 अरब डॉलर तक कच्चे हीरे के आयात में 24.5 प्रतिशत की गिरावट कमजोर वैश्विक बाजारों और कम प्रसंस्करण आर्डर (ठेकों) को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक हीरा सप्लाई चेन को भी प्रभावित किया है। रूस एक प्रमुख कच्चा हीरा उत्पादक है उस पर प्रतिबंधों ने व्यापार को और जटिल बना दिया है।

नई दिल्ली। भारत का हीरा क्षेत्र गंभीर संकट का सामना कर रहा है। पिछले तीन वर्षों में आयात और निर्यात दोनों में भारी गिरावट आई है। इससे बैंक कर्ज के भुगतान में चूक, कारखाने बंद होने और बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने की खतरा पैदा हो गया है। यह बात आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने कही है। हालांकि, निर्यात आय में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ऑर्डर में कमी और प्रयोगशाला में बनने वाले हीरों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कच्चे हीरों का भंडार बढ़ रहा है।

डायमंड सेक्टर काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। दुख की बात यह है कि गुजरात के हीरा उद्योग से जुड़े 60 से अधिक लोगों ने आत्महत्या की है, जो भारत के हीरा उद्योग पर पड़ रहे गंभीर वित्तीय और भावनात्मक दबाव को दर्शाता है।

अजय श्रीवास्तव, जीटीआरआई के फाउंडर

आर्थिक शोध संस्थान के अनुसार, 2021-22 में 18.5 अरब डॉलर से 2023-024 में 14 अरब डॉलर तक कच्चे हीरे के आयात में 24.5 प्रतिशत की गिरावट कमजोर वैश्विक बाजारों और कम प्रसंस्करण आर्डर (ठेकों) को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक हीरा सप्लाई चेन को भी प्रभावित किया है। रूस एक प्रमुख कच्चा हीरा उत्पादक है, उस पर प्रतिबंधों ने व्यापार को और जटिल बना दिया है। इसने वैश्विक हीरा व्यापार को भी धीमा कर दिया है।

जीटीआरआई के फाउंडर अजय श्रीवास्तव का कहना है कि प्रयोगशाला में तैयार किए गए हीरों की ओर उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग प्राकृतिक हीरों की मांग को प्रभावित कर रही है। ऐसा माना जाता है कि प्रयोगशाला में बने हीरे अधिक किफायती और टिकाऊ होते हैं। भारतीय हीरा उद्योग में 7,000 से अधिक कंपनियां शामिल हैं जो हीरे की कटाई, उन्हें तराशने और निर्यात जैसी विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं।

लगातार दूसरे दिन गिरा एयरलाइन कंपनी का स्टॉक, निवेशक क्यों बेच रहे हैं शेयर?

नई दिल्ली। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट शेयरों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। आज भी स्पाइसजेट 6.27 फीसदी गिरकर 69.10 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि आगे भी शेयर में गिरावट आ सकता है।

क्यों गिर रहे हैं शेयर

स्पाइसजेट अभी कर्ज से जूझ रही है। ऐसे में कर्ज की भरपाई के लिए कंपनी फंड जुटाने की कोशिश कर रही है। स्पाइसजेट बोर्ड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिये फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है।

क्यूआईपी के जरिये फंड जुटाने के प्रयास के बाद से कंपनी के शेयर में बिकवाली देखने को मिली है। मार्केट रेगुलेटरी सेबी (SEBI) के अनुसार कंपनी का फ्लोर प्राइस 64.79 रुपये हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी क्यूआईपी के जरिये 500 करोड़ रुपये का फंड जुटाने की योजना बना रही है। इसके अलावा कंपनी वारेंट्स और प्रमोटर्स के जरिये 736 करोड़ रुपये जुटाएगी।

स्पाइसजेट के शेयर परफॉर्मेंस

इस हफ्ते के शुरुआती कारोबार यानी सोमवार को स्पाइसजेट के शेयर (SpiceJet Share Price) 77.79 रुपये प्रति शेयक पर बंद हुआ था। वहीं मंगलवार से अभी तक कंपनी के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा गिर गए हैं। शेयर में स्पाइसजेट कर्ज में डूब गई है। ऐसे में कंपनी के वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कंपनी के बोर्ड ने फंड जुटाने को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने क्यूआईपी के जरिये फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद कंपनी के शेयर में बिकवाली देखने को मिली है। पिछले दो सत्र से कंपनी के शेयर लाल निशान पर बंद हो रहे हैं।

आई गिरावट का असर कंपनी के एम-कैप पर भी पड़ा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के वेबसाइट के अनुसार स्पाइसजेट का एम-कैप (Spicejet M-Cap) 5,483.48 करोड़ रुपये हो गया है।

अगर स्पाइसजेट शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी के शेयर ने 81.65 फीसदी का रिटर्न दिया। वहीं, बीते 6 महीने में कंपनी के शेयर 16.19 फीसदी चढ़ गए।

अमेरिका में घटेंगी ब्याज दरें, पर भारत में उम्मीद नहीं; किस बात से डर रहा आरबीआई?

SBI के नवनियुक्त प्रमुख सीएस शेट्टी का कहना है कि आरबीआई हाल-फिलहाल ब्याज दरों में कटौती नहीं करने वाला। उन्होंने कहा कि नीतिगत दरों में कमी के लिए हमें चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2025) तक इंतजार करना पड़ सकता है। खाद्य मुद्रास्फीति के मोर्चे पर सुधार होने तक रेपो रेट में कमी की संभावना नहीं है। आरबीआई ने फरवरी 2023 से रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है।

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन सीएस शेट्टी का कहना है कि इस बात की कोई संभावना नहीं कि 2024 में आरबीआई ब्याज दरों में किसी तरह की रियायत देगा। उन्होंने इसकी वजह खाद्य मुद्रास्फीति में अस्थिरता को बताया। माना जा रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व चार साल में पहली बार ब्याज दरों में कटौती का एलान बुधवार को कर सकता है। इससे अन्य देशों के केंद्रीय बैंक भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होंगे।

हाल ही में बैंक की कमान संभालने वाले शेट्टी ने एक साक्षात्कार में बताया, 'नीतिगत दरों के मोर्चे पर, बहुत से केंद्रीय बैंक स्वतंत्र रूप से फैसला ले रहे हैं। हालांकि फेडरल रिजर्व द्वारा अगर दरों में कटौती की जाती है तो सभी प्रभावित होंगे। जहां तक आरबीआइ की बात है तो वह ब्याज दरों में कटौती पर फैसला लेने से पहले खाद्य मुद्रास्फीति को ध्यान में रखेगा।'

हमारा मानना है कि चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान दरों में कटौती नहीं हो सकती है। हमें ब्याज दरों में किसी भी तरह की रियायत के लिए चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2025) तक इंतजार करना पड़ सकता है। खाद्य मुद्रास्फीति के मोर्चे पर सुधार होने तक रेपो रेट में कमी की संभावना नहीं है।

आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सात से नौ अक्टूबर के बीच बैठक होनी है। नीतिगत दरों के बारे में फैसला लेते समय एमपीसी खुदरा मुद्रास्फीति को ध्यान में रखती है। जुलाई में यह 3.60 से बढ़कर अगस्त में 3.65 प्रतिशत हो गई थी। हालांकि खुदरा मुद्रास्फीति अभी आरबीआई द्वारा निर्धारित चार प्रतिशत के लक्ष्य के नीचे है। अगस्त में खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि की दर 5.66 प्रतिशत थी।

आरबीआई ने उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच अगस्त में रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा था। यह लगातार नौवीं एमपीसी बैठक थी, जिसमें नीतिगत दर के मोर्चे पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया गया। आरबीआइ ने फरवरी, 2023 से रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है।

पिछली बैठक में, छह में से चार एमपीसी सदस्यों ने यथास्थिति के पक्ष में मतदान किया, जबकि दो बाहरी सदस्यों ने दर में कटौती की वकालत की थी। इस सप्ताह की शुरुआत में आरबीआई गवर्नर दास ने भी कहा था कि ब्याज दर में नरमी का फैसला मासिक आंकड़ों के आधार पर नहीं बल्कि इस बात निर्भर करेगी कि लंबे समय तक खाद्य मुद्रास्फीति कैसी रहती है।

सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी के विनिवेश पर विचार नहीं

अपनी कुछ सहायक कंपनियों में एसबीआई की हिस्सेदारी के मुद्रीकरण पर शेट्टी ने कहा कि वर्तमान में किसी भी सहायक कंपनी में हिस्सेदारी के विनिवेश के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'अगर इन सहायक कंपनियों को (विकास) पूंजी की आवश्यकता होती है, तो हम निश्चित रूप से जांच करेंगे।'

उन्होंने कहा कि इस समय, किसी भी बड़ी सहायक कंपनी को अपने परिचालन को बढ़ाने के लिए मूल कंपनी से पूंजी की आवश्यकता नहीं है। बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में एसबीआइ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 489.67 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी डाली थी। कंपनी ने कर्मचारियों को शेयर भी आवंटित किए थे और इसके परिणामस्वरूप बैंक की हिस्सेदारी 69.95 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 69.11 प्रतिशत हो गई है।

झिलमिलाती झांकियों का रंगीन कारवां

हरिहर सिंह चौहान

' अनंत उंमगता परम्परा का उजाला और संस्कृति का प्राचीनतम गणेश विसर्जन चल समारोह को रतजगा में 5 लाख से अधिक लोगों की एकजुटता भाईचारा और नारीशक्ति की समरसता के कौशल को दिखने हेतु बेटीयों ने भी रंग जमाया। शास्त्र कलां में बेटीयों ने भी तलवार भाला बनेठी चलाईं। 26 झांकियों में 15 मिलों की व 11 सरकारी झांकी भी थी ।वहीं 92 अखाड़ों ने आत्मरक्षा व शौर्य का प्रदर्शन पूरी रात किया। 101 वर्षों की गौरवशाली परंपरा की यह झिलमिलाती झांकियों का कारवां मेहनतकश मजदूर का आशीर्वाद आज भी इन्दौर को मिल रहा है। तभी तो सार्वजानिक उत्सव का यह उल्लासपूर्ण उत्साह का सराबोर में हम इन्दौरी पूरी दुनिया में सबसे अलग है।

एक शुरुआत की लोकमान्य तिलक ने

वह लोक उत्सव को दानवीर हुकुमचंद जी ने बढ़ाया आगे

पसीने की कीमत को बना सिरमौर

उन्हीं मजदूरों को आगे बढ़ाया

जीवन में उंमगता व उल्लास का रंग भर कर

उन्हें अपनी संस्कृति परम्परा से जोड़कर

गणेश विसर्जन लोक उत्सव को हम इन्दौरीयो ने मनाया।

बेदांत कंपनी पर भवानीपटना विधायक सागर दास नाराज़ जताई

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: लांजीगढ़ में वेदांता कंपनी के लाल मिट्टी के तालाब की ढह गया को लेकर भवानीपटना विधायक सागर दास घुसे हुए । पिछले रविवार को वेदांता एलुमना कंपनी का लाल मिट्टी का तालाब ढह गया। परिणामस्वरूप, स्थानीय क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ भूमि लाल पानी से भर गई है। साथ ही इस लाल पानी ने पास की नदी में मिलकर उसे जहरीला बना दिया है।कल यह खबर मिलने के बाद स्थानीय कांग्रेस विधायक सागर दास घटनास्थल पर गये और नुकसान का आकलन किया. उन्होंने कमजोर लोगों की समस्याओं को भी समझा। बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि वेदांता कंपनी को सात दिन के अंदर हैरिगैस्ट को समझने को कहा गया है। अन्यथा उन्होंने धमकी दी है कि भविष्य में वेदांता के खिलाफ आंदोलन किया जायेगा। हालाँकि, जब वह कमजोर लोगों से बात कर रहे थे, तो सभी ने वेदांत की मनमानी कार्रवाइयों के बारे में बात की। वेदांता के खिलाफ कोई शिकायत करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है। परेशान लोगों ने विधायक से शिकायत की , पुलिस तैनात की जा रही है। हालांकि इस बारे में वेदांता कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।

वन नेशन, वन इलेक्शन को मंजूरी: 191 दिन में तैयार रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए, कैसे बदलेगी चुनाव व्यवस्था; इससे देश का क्या फायदा?

मोदी कैबिनेट नेवन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिससे पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू होने से देश में क्या बदलेगा क्या फायदा होंगे पढ़िए ऐसे ही 12 सवालों के जवाब...

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने आज यानी बुधवार को एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब देश की 543 लोकसभा सीट और सभी राज्यों की कुल 4130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की राह खुल गई। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

इससे एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हर हाल में 2029 से पहले लागू होगा। इसके एक दिन बाद ही एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के क्या मायने हैं? वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े 12 सवालों के जवाब यहां पढ़िए...

78 वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्रचार से पीएम मोदी ने कहा-

देश में हर छह माह में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। ऐसे में देश को आगे ले जाने के लिए वन नेशन, वन इलेक्शन को आगे लाना ही होगा।

मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह -

हमारी योजना इस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कराने की है। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं।

क्या है वन नेशन वन इलेक्शन?

एक देश एक चुनाव यानी (One Nation, One Election) का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हों। ऐसे समझिए, देश की सभी 543 लोकसभा सीटों और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 4130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। वोटर सांसद और विधायक चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर अपना वोट डाल सकेंगे।

क्या है मौजूदा चुनाव व्यवस्था?

देश में अभी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं।

क्या यह चुनाव व्यवस्था देश के लिए नई है?

नहीं, यह कांसेप्ट भारत के लिए नया नहीं है। देश में आजादी के बाद 1952 से लेकर 1957, 1962 और 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं तय समय से पहले भंग कर दी गई थीं। 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई थी। इसके चलते एक देश एक चुनाव की गाड़ी पटरी से उतर गई।

कमेटी ने कितने दिन में तैयार की रिपोर्ट?

वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सितंबर, 2023 को एक कमिटी गठित की गई थी। इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे थे। कमेटी के सदस्यों ने सात देशों की चुनाव व्यवस्था का अध्ययन किया।

स्टेकहोल्डर्स-एक्सपर्ट्स से चर्चा और रिसर्च के बाद 191 दिन में 18 हजार 626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई। कमेटी ने यह रिपोर्ट 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई। रिपोर्ट में सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है।

वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी कितने और कौन-कौन है सदस्य?

पूर्व राष्ट्रपति, एक वकील, तीन नेता और तीन पूर्व अफसर समेत आठ लोग कमेटी के सदस्य हैं।

रामनाथ कोविंद, अध्यक्ष (पूर्व राष्ट्रपति)

हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता

अमित शाह, गृह मंत्री (बीजेपी)

अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस नेता

गुलाम नबी, डीपीए पार्टी

इनके सिंह, 15वें वित्त आयोग पूर्व अध्यक्ष

डॉ. सुभाष कश्यप, लोकसभा के पूर्व महासचिव

संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त

कमेटी ने क्या सुझाव दिए?

सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए।

पहले चरण में लोकसभा-विधानसभा चुनाव और फिर दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं।

चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड बनाए।

देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग करने की भी सिफारिश की है।

वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के क्या फायदे हैं?

लोकसभा के पूर्व सचिव एस के शर्मा बताते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से कई फायदे होंगे। जैसे-

चुनाव खर्च में कटौती: देश में बार-बार चुनाव कराने पर लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और जनशक्ति समेत कई चीजों पर बहुत पैसा खर्च होता है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में अनुमानित कुल खर्च करीब 1.35 लाख करोड़ रुपये तक हुआ है, जोकि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में बहुत अधिक है। 2019 में 60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। अगर राज्यवार विधानसभा व स्थानीय चुनाव का खर्च भी जोड़ा जाए तो अंदाजा लगाइए कि ये खर्च कितना होगा। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने पर चुनाव खर्च में कम होगा।

प्रशासनिक कार्यक्षमता में वृद्धि: चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने से नीति निर्माण और विकास कार्यों में रुकावट आती है। अगर पांच साल में सिर्फ एक बार आचार संहिता लागू होगी तो स्वाभाविक है कि प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।

देश में हर छह माह चुनाव होने पर प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षाबलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है।

लुभावने वादे नहीं आएंगे काम : बार-बार चुनाव लोकलुभावन नीतियों को बढ़ावा देते हैं। एक साथ चुनाव लंबी अवधि की नीति योजना और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मददगार साबित होंगे।

वोट प्रतिशत में वृद्धि: एक साथ चुनाव होने से मतदाता एक ही समय में कई वोट डाल सकते हैं, जिससे मतदाता भागीदारी में वृद्धि हो सकती है।

वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में चुनौतियां क्या हैं?

लोकसभा के पूर्व सचिव एसके शर्मा बताते हैं कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान में कई संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी।

क्षेत्रीय दल क्या कर रहे हैं विरोध?

विपक्षी दल जैसे - कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बसपा और सपा इसका विरोध करते इस असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी करार देते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय दल को डर है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख हो जाएंगे और वे स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा नहीं पाएंगे।

साल 2015 में IDFC की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर 77 % संभावना इस बात की होती है कि मतदाता राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी को चुनते हैं, जबकि अलग-अलग चुनाव होने पर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी को चुनने की संभावना घटकर 61% हो जाती है।

इन देशों में लागू है यह चुनाव व्यवस्था

दक्षिण अफ्रीका

स्वीडन

बेल्जियम

जर्मनी

फिलीपींस

लोकसभा सीटों की संख्या 750 होगी?

देश में अभी 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होता है। साल 2029 में होने वाले चुनाव से पहले जनगणना होती है तो परिसीमन भी होगा।

ऐसे में चर्चा यह है कि साल 2029 में होने वाला लोकसभा चुनाव परिसीमन के बाद 543 की बजाय लगभग साढ़े सात सौ सीटों पर होगा। इनमें से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुताबिक, एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

हालांकि, लोकसभा सीटों को बढ़ाने को लेकर दक्षिण के राज्य विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर समान जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों पर निर्धारण होता है तो लोकसभा में दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व गिर सकता है, जिस कारण वे विरोध कर रहे हैं। बता दें कि उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या की बढ़ोतरी कम हुई है।

देश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं?

मौजूदा समय में देश के 28 राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4130 विधानसभा सीटें हैं। सबसे अधिक विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 403 हैं तो सबसे कम राज्य के हिसाब से सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़कर देखें तो पुडुचेरी में 30 सीटें हैं।

यहां देखें किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें...

राज्य	विधानसभा सीटें
आंध्र प्रदेश	175
अरुणाचल प्रदेश	60
असम	126
बिहार	243
छत्तीसगढ़	90
गोवा	40
गुजरात	182
हरियाणा	90
हिमाचल प्रदेश	68
झारखंड	81
कर्नाटक	224
केरल	130
मध्य प्रदेश	230
महाराष्ट्र	288
मणिपुर	60
मेघालय	60
मिजोरम	40
नगालैंड	60
ओडिशा	147
पंजाब	117
राजस्थान	200
सिक्किम	32
तमिलनाडु	234
तेलंगाना	119
त्रिपुरा	60
उत्तर प्रदेश	403
उत्तराखंड	70
पश्चिम बंगाल	294

केंद्रशासित प्रदेश

केंद्रशासित प्रदेश	विधानसभा सीटें
दिल्ली	70
पुडुचेरी	30
जम्मू-कश्मीर	90

परिसीमन क्या होता है?

देश या राज्य में लोकसभा या विधानसभा सीटों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। इसका उद्देश्य जनसंख्या में हो रहे बदलाव के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को संतुलित करना है ताकि प्रत्येक लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में एक समान संख्या में मतदाता हों।

इस प्रक्रिया को करने वाली संस्था को परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) के रूप में जाना जाता है।

परिसीमन कब होता है?

सामान्य तौर पर हर जनगणना के बाद परिसीमन किया जाता है, जिससे जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का संतुलन बनाया जा सके। हालांकि, देश में 1976 से परिसीमन पर पाबंदी लागू थी।

साल 2002 में परिसीमन आयोग का पुनर्गठन हुआ और 2008 में परिसीमन कराया गया। अगला परिसीमन 2026 में होने की संभावना है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023